replies in respect of Chapter V of the 8th Action Taken Report (Thirteenth Lok Sabha) on 1st Report (Thirteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants 2000-2001 of the Ministry of Railways.'

REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Thirty-second Report of the Standing Committee on Finance (Thirteenth Lok Sabha) on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Fourteenth Report of the Committee on Demands for Grants (2001-2002) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

REPORT OF THE COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) : सभापति महोदय, मैं 'स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रशिक्षण और अधिकारिता' (तेरहवीं लोक सभा) के संबंध में महिला अधिकारिता संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ ।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Securities Scam in Co - Operative Banks

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के कोपरेटिव बैंकों में जो सिक्यूरिटीज स्कैम हुआ है, उसकी तरफ और उसमें केन्द्र सरकार की जो रेगुलेटिंग एजेन्सी हैं उनकी असफलताओं की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Chairman, Sir, as per the information available with the Reserve Bank of India, seven Cooperative Banks in Maharashtra had entered into transactions in Government securities and the amount involved are:

Nagpur DCCB -- Rs.153.04 crores; Wardha DCCB -- Rs. 25 crores, Osmanabad DCCB -- Rs.29.99 crores, Sadguru Jangli Maharaj UCB -- Rs.40 crores, Amravati Peoples Cooperative UCB -- Rs.9.50 crores, Swarnayug UCB -- Rs.5.79 crores and Raghuvanshi UCB -- Rs.5.40 crores.

The banks paid the amounts to the brokers purportedly for acquiring Government securities, but no such securities were acquired or delivered.

The transactions involved M/s Home Trade Ltd. and four other brokers, viz. Indramani Merchant Ltd.,Kolkata, Syndicate Management Services Ltd., Ahmedabad, Giltedge Management Services Ltd., Mumbai, and Century Dealers P. Ltd., Mumbai.

RBI has laid down detailed guidelines under which all transactions in Government securities are to be undertaken only through SGL account where available but in most of these banks, despite their having an SGL/constituent SGL account, transactions have been undertaken in the physical mode and the physical delivery of the securities have not been taken. RBI guidelines further stipulate that the banks may undertake securities transactions among themselves or with non-bank clients only through members of NSE, OTCEI and BSE. In the above-mentioned transactions, however, none of these brokers were members of debt market segment of any of the exchanges. The transactions were continued to be undertaken despite no security being delivered in physical or scripless form. The payments were made directly to the brokers who acted as counter parties in these transactions.

There has been no failure on the part of the regulators as alleged. Detailed guidelines have been laid down by the regulators and the violations were detected during Inspection and Surveillance and prompt action taken. These transactions had come to the light in course of regular statutory inspections of Nagpur and Osmanabad DCCBs by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and as a follow up on off-site surveillance/market intelligence reports over urban cooperative banks by RBI. These transactions were manifestly fraudulent transactions and do not reflect in any way on adequacy of regulatory guidelines. Further scrutiny revealed absence of any investment policy as per RBI guidelines, non-existence of concurrent audit/internal inspection system, lack of trained staff and complete failure of the management, especially the board of directors, in controlling, guiding and monitoring the affairs of the bank and failure to comply with the RBI guidelines. In view of the manifest fraudulent transactions in violation of its guideline and to forestall any further damage by the existing board of directors, RBI sought supersession of the board of directors of Nagpur, Osmanabad and Wardha DCCBs and Sadguru Jangali Maharaj and Amravati UCBs under section 110 A(iii) of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960. The board of directors of these banks, who were elected by its members but had failed in discharging their duties, have since been superseded. RBI has also asked the Registrar of Cooperative

Societies of Maharashtra to conduct special audit of investment transactions of cooperative banks. Meanwhile, Government of Maharashtra has filed criminal complaints against the brokers/Chairmen of these five co-operative banks. SEBI has also issued order under section 11 and 11B of SEBI Act, 1992 debarring M/s Home Trade Ltd. from dealing in securities.

श्री संजय निरुपम : आदरणीय सभापति जी, मेरे ख्याल से इस सदन में हम जितने भी लोग बैठे हैं, सबने हिन्दी फिल्में देखी होंगी । हर हिन्दी फिल्म में हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ी हत्या या हिंसा हो जाती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है । हम बार-बार सोचते हैं कि हत्या या हादसा होने से पहले ....

MR. CHAIRMAN: Mr. Sanjay Nirupam, there are a number of Members who want to speak. You should put pointed questions so that they can also be covered.

SHRI SANJAY NIRUPAM: Sir, I will try my best to put pointed questions.

MR. CHAIRMAN: It will be easier for the Minister also to reply. And all the Members who want to speak can also be covered. No background need be given. He knows the background, you know the background and Members know the background.

श्री संजय निरुपम : मैं कोशिश करता हूं, सर ।

सभापति जी, मेरा कहना यह है कि गाइडलाइंस हैं, सारे नियम-कानून हैं लेकिन इसके बावजूद घोटाले हो जाते हैं और घोटाले हो जाने के बाद हमें होश आता है और हम सोचते हैं कि यह क्या हो गया । आरबीआई के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस तरह के उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को निर्देश दिए, यह सारी जानकारी हमारे पास है । हमें बुनियादी तौर पर जो बताना है, वह यह है कि हमारे देश में और खास तौर से मुम्बई में दो तरह की मार्किट हैं -- एक इक्विटी मार्किट और दूसरी डेट मार्किट । इक्विटी मार्किट के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लगातार इतने घोटाले हुए, इतना हमने शोर मचाया तो इक्विटी मार्किट के लिए हमने व्यवस्थाएं कीं, लेकिन डेट मार्किट के लिए जो पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था आज नहीं है । मुम्बई के जो कोआपरेटिव बैंक थे और महाराष्ट्र के जो कोआपरेटिव बैंक थे, उन्होंने गवर्नमेंट की सिक्युरिटी खरीदी और जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि बगैर फिज़िकल डिलीवरी के पैसे दे दिए गए ।

सभापति महोदय, यह लगभग 503 करोड़ रुपए का घोटाला है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, वे अधूरे हैं, वे बहुत कम हैं । जिस तरह से रामायण में किस्सा है कि हनुमान की पूंछ का कोई अंत समझ में नहीं आता था, उसी तरह से यह घोटाला हजार करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है । लेकिन फिर भी अपने-अपने ढंग से कुछ फिगर्स दी गई हैं । ये फिगर्स अधूरी हैं, कम हैं और उसका बुनियादी कारण यह है कि अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चल रहा है ।

महोदय, सबसे पहले नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम सामने आया और नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट से उसके बारे में पता चला । उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद पता चला कि इनका 125 करोड़ रुपए के आस-पास पैसा डूब गया है और इनके पास गवर्नमेंट सिक्यूरिटी नहीं आई है । बाद में पता चला कि यह राशि डेढ़ सौ करोड़ रुपए है और उसके बाद धीरे-धीरे अन्य बैंकों के नाम सामने आए । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह का केस, हर्षद मेहता केस हुआ था । महोदय, जब वित्तीय संस्थाओं के पैसे जाते हैं तो पैसे तो हम दे देते हैं लेकिन सिक्यूरिटी आने में बहुत समय लगता है । हमारे पास जैसे शेयर मार्केट में रोज की एक व्यवस्था है कि रोज शाम को आपको यह पता चल जाएगा कि आज क्या-क्या लेनदेन हुआ और किसने कितने पैसे डाले, यह पता चल जाता है । सचमुच इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, यह पता नहीं चलता है लेकिन रोज के कारोबार के बारे में पता चल जाता है । डैट मार्केट में आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । वहां ज्यादातर कारोबार फोन के जरिए हो रहा है । उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है । वह सारा कारोबार फोन के जरिए होता है और बड़े-बड़े लैजर मैंटेन किए जाते हैं । मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि RBI के जरिए, नाबार्ड के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे रोज की सिक्यूरिटी ट्रेडिंग के बारे में शाम को पता चल सके कि सचमुच किस डिपार्टमेंट की, किस पब्लिक सैक्टर की, किस विभाग की सिक्यूरिटी कहां गई है और कितने पैसे में गई है । यह व्यवस्था आज की तारीख में नहीं है जब कि हमारे पास सारी रेगुलेटिंग गाइडलाइंस हैं । इसी वजह से हर्षद मेहता स्कैम हुआ था । यहां बड़े-बड़े वित्तीय जानकार बैठे हैं, वे जानते हैं कि वह स्कैम इसी वजह से हुआ था । उन्हीं खामियों का उपयोग होम ट्रेड नामक एक कंपनी ने किया है। तो यह जो टाइम गैप है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं चाहूंगा कि वे इस बारे में स्पष्ट तौर पर अपनी राय दें ।

महोदय, कोऑपरेटिव बैंकों में जो बैंक घोटाले हुए, उनके बारे में RBI की गाइडलाइंस तो थीं लेकिन उन पर RBI की नज़र नहीं थी । यह पिछले 2 सालों से चल रहा है और 2 सालों तक चलता रहा । इन 2 सालों में 503 करोड़ रुपए का घोटाला तो मुझे ही दिखाई दे रहा है । ये सारे के सारे पैसे कहां गए, यह अभी तक पता नहीं चला है । पहला प्रश्न यह है कि घोटाला आखिर कितना बड़ा है, इस बारे में कोई नहीं बता रहा है । दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर घोटाले का पैसा कहां गया ? 503 करोड़ रुपए का घोटाला जो मैं बता रहा हूं, आखिर वह पैसा कहां गया, किसने लिया ? होम ट्रेड वाले बता रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। क्या इस पूरे घोटाले का कोई नाता मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज स्कैम से है? इस बात की छानबीन होनी चाहिए । इस बात की छानबीन महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर सकती । आपने यह पूरा का पूरा मामला महराष्ट्र पुलिस पर छोड़ दिया । महाराष्ट्र पुलिस के नागपुर यूनिट के इंस्पैक्टर ने संजय अग्रवाल को गिरफ्तार किया । संजय अग्रवाल, होम ट्रेड के डॉयरेक्टर हैं। जब वे गिरफ्तार हुए और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने pay-in, pay-out, money settlement और इस तरह की अन्य टैक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया, जिन्हें सुनकर इंस्पैक्टर परेशान हो गए कि इनका मतलब क्या है । यानी इस तरह के स्कैम्स की छानबीन के लिए हमें टैक्निकल जानकारी रखने वाले जांचकर्ता या जांच एजेंसी की आवश्यकता है ।

महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले की छानबीन CBI के जरिए होनी चाहिए । महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी जिस तरह से छानबीन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं निकलकर आने वाला है । महाराष्ट्र सरकार ने पिछले एक महीने में जिस तरह की भूमिका निभाई है, वह भी संदेहास्पद है । महोदय, अप्रैल महीने के अंत में बताया गया कि आपके कोऑपरेटिव बैंकों में इस तरह का स्कैम हुआ है, आप जल्दी इस पर ऐक्शन लीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस पर ऐक्शन लेने में लगभग 15 दिन लग गए और 15 दिनों तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई ऐक्शन नहीं लिया । उसके बाद श्री सुनील केदार, जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जो सबसे पहला अभियुक्त है, जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया है, उसको गिरफ्तार करने में 15 दिन और लगे । जब होम ट्रेड कंपनी का नाम निकलकर आया तो ...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): संजय जी, आप बार-बार महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने इसमें कहीं भी विलंब नहीं किया । जिस दिन इस मामले को उनके नोटिस में लाया गया, उसके दूसरे दिन सुनील केदार अरेस्ट हुए और दूसरे दिन के बाद वहां के बोर्ड को डिज्ज़ॉल्व करने की कार्यवाही महाराष्ट्र सरकार ने की ।

इसमें कोई आरबीआई या रेगुलेटर का सवाल नहीं था। आपने राज्य सरकार का नाम लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इसको पॉलिटिकल कलर देना चाहते हैं तो बात अलग है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, वहां पर दोनों की हुकूमत है, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री जिनके पास कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है, उन्होंने इमीडियेटली उस पर एक्शन लिया है और एनसीपी जिसके पास होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर ने भी एक्शन लिया है।

श्री संजय निरुपम : यह हो सकता है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल : मैं एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि इसमें सारे कांग्रेस और एनसीपी के लोग इनवाल्व हैं तो यह गलत है। यह जंगली महाराज कोआपरेटिव बैंक में आपसे संबंधित लोग ही हैं।

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, मैंने अभी तक किसी पक्ष का नाम नहीं लिया है, किसी पॉलिटीकल पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी पॉलिटीकल पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप स्कैम के बारे में जरूर बोलिए। इसकी जितनी गहराई में आप जाना चाहते हैं, उतनी ही गहराई में हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन आपने महाराष्ट्र सरकार के बारे में कहा है, इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैंने अभी तक किसी पॉलिटीकल पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया है, किसी पॉलिटीकल पार्टी का नाम नहीं लिया है। लेकिन क्या यह संयोग है कि

नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं, वह एनसीपी के बहुत एक्टिव लीडर हैं, वे चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे, क्या यह संयोग है कि उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन मिस्टर * वह आपकी सरकार के सिंचाई मंत्री * के रिश्तेदार हैं, भाई हैं। क्या यह संयोग है कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन * महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक के चैयरमैन * जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके सगे भाई हैं? यह सब संयोग नहीं है। इसीलिए हमें शक हो रहा है कि सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन घोटालेबाजों को बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : जंगली महाराज कोआपरेटिव बैंक में सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं और उसके एक्टिव मेम्बर्स हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : ठीक है। मैं यह नहीं बोल रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप क्या कहना चाहते हैं ? 100 करोड़ रुपया शीमैन के प्राविडेंट फंड का गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर जनरल शिपिंग जो होते हैं, वह उसके चेयरमैन होते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वाल्वड है। आप इसको पॉलिटिकल मत करिए। अगर कोई हादसा हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उसकी गहराई में जाना जरूरी है। अगर आप यह कहना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग इसमें इन्वाल्वड हैं तो उसमें पूरी पार्टी का भी दोष है। यह बिल्कुल गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): सभापति महोदय, माननीय सदस्य किस नियम के तहत बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, मेरे पास समय कम है। अगर इस तरह से मुझे डिस्टर्ब किया जायेगा तो मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): सभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL: He is mentioning the name of my party and leaders. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: When he is making certain allegations against them, I cannot keep quiet. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You will get an opportunity. ...*(Interruptions)*...

श्री राजू परमार (गुजरात): सभापति जी, जो लोग डिफेंड नहीं कर सकते हैं, उनके नाम यहां हाउस में लिये जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : सभापति जी, जो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance. ...*(Interruptions)*... I will give you a chance. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: I will speak, Sir. But he should stop speaking like this. ...*(Interruptions)*... He should not mention the name of my party and my leaders. What is he informing the House?

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: What is he informing the House? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I appreciate that. But he should also refrain from mentioning the name of my party and people. We all want a probe into the scam. I am also for a CBI probe, as he is. Be he should not do like this.

श्री संजय निरुपम : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं अपनी आशंका ज़ाहिर कर रहा था। पिछले एक महीने में जिस तरह से जांच की कार्यवाही हुई है, वह संतोषजनक नहीं है। मैंने कहा कि जब आरबीआई ने बताया, जब नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट आई, उसके 10 दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। उसके भी 10 दिन बाद सुनील केदार को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 14 दिन तक संजय अग्रवाल जो कि होम ट्रेड का मुख्य प्रमोटर है, वह फरार रहता है। वह मुम्बई से प्लेन का टिकट लेता है और प्लेन से वह नागपुर में उतरता है और एक होटल में ठहरता है। उसके बाद पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ उसका सरेंडर कराया जाता है। यह सब कुछ जो चल रहा है, यह संदेह के बीज़ पैदा करता है, इसमें संदेह का बीज़ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल हैं। प्रफुल जी, एतराज़ करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक की साल-डेढ़ साल पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सभी बैंकों के चेयरमैन को बुलाया गया था। यह जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक है, इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं, आप इसे संयोग कहिए या दुर्योग कहिए, वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उन सारे चेयरमैन को बिठाया गया, उनको संजय अग्रवाल से मिलाया गया और यह बताया गया कि यह संजय अग्रवाल है, इनकी होम ट्रेड नाम की कम्पनी है । **...(व्यवधान)...**

श्री प्रफुल्ल पटेल : आपके पास इस बात की जानकारी है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री संजय निरुपम : मेरे पास जानकारी है। मैं सही जानकारी दे रहा हूं। मैं कभी गलत जानकारी नहीं देता हूं । **...(व्यवधान)...**

श्री प्रफुल्ल पटेल : यह बिल्कुल गलत बात है । हर चीज में फिल्मी डॉयलग मारकर अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो वह अलग बात है ।

श्री राजू परमार : अभी जो बात बतायी जा रही है, उसकी ओथैंटीसिटी क्या है ? ...**(व्यवधान)**...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): प्वाइंटिड क्वेश्चन करेंगे लेकिन प्वाइंटिड क्वेश्चन हुए ही नहीं । ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have to put questions to the Minister. There should not be any mutual incrimination. There should not be any mutual charging. You should not charge each other. You have to put specific questions and the Minister would answer those questions. ...*(Interruptions)*... I will permit you. But let the discussion go on smoothly.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I appreciate it. But he should also be restrained from making such allegations. He is talking of a Board meeting. Does he know who was there at the meeting? He said, "In the Maharashtra State Cooperative Board meeting Sanjay Aggarwal was produced to make a representation to the Board." How does he know it? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I cannot say anything. You will be given a chance to speak. Then you can reply to all the charges he is making and answer the questions which he is putting to the Minister. Let us not charge each other in the House.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I would like to make a request to the hon. Members. Some of us are also slated to speak on this issue. There are going to be very serious repercussions of what has happened. There has been a regulatory failure also. A lot of things have been done. A lot of money deposited by the people in the cooperative banks and a lot of money of the workers which was kept in the Provident Fund has gone into the scam and has vanished. It is not proper on our part to behave in a manner in which we are behaving by making allegations and counter-allegations. There are a lot of systemic aspects. We should discuss it along those lines.

MR. CHAIRMAN: Mr. Nirupam, kindly put specific questions.

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, मुझो यह निवेदन करना है कि सी.बी.आई. की इन्क्वायरी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ तो लॉजिक देना पड़ेगा ।

श्री सभापति : आपको लॉजिक देने की जरूरत नहीं है । मिनिस्टर साहब जानते हैं, हर मैंबर जानते हैं, लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं । The Members should use discretion while speaking.

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं कि इस पूरे मामले की छानबीन में कहीं पर भी मुम्बई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का नाम नहीं आया। मैं सदन में बाकायदा एक डाक्यूमेंट रखने के लिए तैयार हूं । यह डाक्यूमेंट किसका है । मुम्बई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में कम से कम चार सौ करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है, यह पैसा डूब चुका है । यह किसी को मालूम नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। जो इनफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, अगर इसमें से एक परसेंट भी इनफॉर्मेशन गलत होगी तो जो सजा होगी, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं । यह मुम्बई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुम्बई के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स की एक ऐपेक्स बॉडी है । मुम्बई के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अपना पैसा इस बैंक में डालते हैं और सुबह शाम जितनी भी जरूरत पड़ती है, उससे पैसा निकालते हैं । इस बैंक में कम से कम 800 करोड़ रुपए अब तक इधर उधर हो चुके हैं। जो थोड़ी सी इनफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, वह यह है कि मध्य प्रदेश की एक डैवलपमेंट कारपोरेशन के लिए इस बैंक ने सौ करोड़ रुपये का लोन दिया । मध्य प्रदेश की वह कम्पनी आज सिक हो चुकी है, वह पैसा वापिस आने वाला नहीं है । इस बैंक ने, मुम्बई कोऑपरेटिव बैंक ने गुजरात में अहमदाबाद स्थित मफतलाल की एक सिक कम्पनी के लिए 70 करोड़ रुपये दिये, वह कम्पनी सिक हो चुकी है, वह पैसा वापिस आने वाला नहीं है । इस बैंक के ऊपर आज किसका कंट्रोल है - प्रफुल्ल भाई को तकलीफ हो जाएगी - नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स का ।(इसके चेयरमैन हैं । * कभी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे । ये * क्या करते हैं ? मुम्बई कोऑपरेटिव बैंक का पैसा लेकर अहमदनगर की शुगर फैक्ट्रीज़ में डालते हैं, वहां दस-दस करोड़ रुपये डालते हैं और उन शुगर फैक्ट्रीज़ के मालिक कौन हैं - राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स । * यहां से दस करोड़ लेते हैं और * इनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता हैं...(व्यवधान)...

SHRI PRAFUL PATEL: He is quoting certain things which are not relevant. Sir, there is no scam in the Maharashtra Cooperative Bank. He is misleading the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANJAY NIRUPAM: Sir, how can he challenge me? I am giving this information.

SHRI PRAFUL PATEL: He should place the facts on the Table of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANJAY NIRUPAM: I am going to place the facts on the Table of the House.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, let him first authenticate these things. If he is willing to authenticate it, I will keep quiet. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANJAY NIRUPAM: Sir, I never say anything which is not authenticated. Please try to understand it.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI PRAFUL PATEL: And you will authenticate it; right?

SHRI SANJAY NIRUPAM: I told you, I am going to authenticate this information.

श्री मूल चन्द मीणा : सभापति महोदय, जिस बैंक का नाम लिया जा रहा है, मंत्री महोदय की स्टेटमेंट में उसका नाम कहीं नहीं है।...(व्यवधान)... मिनिस्टर की स्टेटमेंट में उसका नाम कहीं नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : इस तरह से आप कितना समय बरबाद कर रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN: Members should seek clarifications rather than make allegations...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: Unnecessarily, he has gone from one to the other. I can also allege that the State Bank of India is doing this; the Bank of Baroda is doing that and so on. Sir, he has to speak on the subject of the Calling-Attention Motion. He cannot raise any other issue ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Nirupam, I told you to be brief.

श्री संजय निरुपम : इतना बड़ा स्कैम है, इतना पैसा डूबा हुआ है और आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं ब्रीफ में बोलूं । मैं इतना बड़ा स्कैम लेकर आया हूं जिस पर महाराष्ट्र सरकार की नज़र नहीं है, जिस पर वित्त मंत्रालय की नज़र नहीं है और मुझे बोला जा रहा है कि मैं चुप रहूं ? सर, इस तरह से डिस्टरबैंस नहीं होनी चाहिए ।

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, is he authenticating all that he is saying?

SHRI SANJAY NIRUPAM: Yes, Sir. लेकिन मुझे कम से कम पढ़कर तो बताने दीजिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप authenticate करेंगे क्या ?

श्री संजय निरुपम : आप इस चीज़ से क्यों डर रहे हैं ? आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि मेरे authenticate करने से आपके घोटाले सामने आ जाएंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : मुझे कोई डर नहीं है ।

श्री संजय निरुपम : तो आप बैठिए, मुझे authenticate करने दीजिए । मैं कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**....

श्री प्रफुल्ल पटेल : आपको जब कहा तब आप authenticate कर रहे हैं ।

श्री संजय निरुपम : मैंने आपके बोलने से पहले ही कहा कि मैं इसे authenticate करने जा रहा हूं, मैं यह डॉक्युमेंट इस सदन में रखने जा रहा हूं । महोदय, इसमें जो दूसरी बड़ी खतरनाक इनफॉर्मेशन है, मैं उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा । ...**(व्यवधान)** ...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता (बिहार): मान्यवर, इन दो बड़े नेताओं के बीच में हम लोगों के इश्यू रह जाएंगे ।

श्री संजय निरुपम : मुम्बई कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आगे देखिए कि इनफॉर्मेशन क्या है, मंत्री जी, आप ज़रा ध्यान दीजिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): कौन सा डॉक्युमेंट है, पहले वह तो बता दीजिए ।

श्री संजय निरुपम : मुम्बई कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आगे जो इनफॉर्मेशन दी गई है, another major scandal ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I am on a point of order. This Motion has been admitted under rule 160, as per which the Minister has made a statement. Now, the Members are entitled to seek clarifications on the basis of the statement of the hon. Minister. No new issue, no new organisation, can be brought within the purview of this discussion...

MR. CHAIRMAN: Yes, you are right.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If the Member wants to have a discussion on any new organisation, or any new issue, he can do so by bringing it separately. But, so far as the clarifications are concerned, these must be confined to the statement which the hon. Minister has made in response to the Calling-Attention Motion.

MR. CHAIRMAN: What he is saying is right. Mr. Nirupam, you should only seek clarifications. It is not a discussion, but it is a Calling-Attention Motion on a certain subject. And, before reading the document, you had not taken permission, and you have not authenticated it. You confine yourself only to clarifications on the basis of the statement of the hon. Minister and nothing else..*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: What he has said should be expunged from the record.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं बहुत ज्यादा रूल्स-रेग्युलेशन्स नहीं जानता, नियम-कानून नहीं जानता लेकिन मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा जो विषय है, वह यह है कि महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक में जो सिक्योरिटी स्कैम हुआ है, उसकी ओर मुझे माननीय

मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है । मैं महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बता रहा हूं, मैं महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा रहा हूं ।

श्री सभापति : बताना नहीं है, you have to seek only clarifications; no explanation, but clarifications on the statement. It is not a debate where you take point-wise and speak.

श्री संजय निरुपम : ऐसा पहली बार नहीं हुआ है । मेरे लिए हमेशा नए-नए नियम-कानून बनते रहे हैं ।

श्री सभापति : नए नहीं हैं ये रूल्स ।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मुझे मंत्री महोदय से यह निवेदन करना है कि संजय अग्रवाल को गिरफ्तार करने में जिस तरह से 14 दिन लगे, बिलकुल उसी तरह से 10 दिन केतन सेठ को गिरफ्तार करने में लगे । केतन सेठ की कंपनी "गिल्टेज मैनेजमेंट" के नाम पर पहली बार नागपुर में केस रजिस्टर हुआ । "गिल्टेज मैनेजमेंट" के मालिक को, उसके मुख्य प्रमोटर को 10 दिनों तक क्यों भटकने दिया गया ? उसके सारे दफ्तरों पर रेड क्यों नहीं डाली गई ? अभी परसों यानी मंगलवार को उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया और वह भी सी.बी.आई. ने प्रोविडेंट फंड के केस में उनको गिरफ्तार किया । कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । उनके दफ्तर में क्या पेपर्स हैं, क्या डॉक्युमेंट्स हैं, जब तक हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम इस घोटाले के बाकी आयामों को नहीं समझा सकते हैं ।

महोदय, तीसरा मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि होम ट्रेड कंपनी में जो तीसरा डायरेक्टर है, *वह मिसिंग है । पता नहीं वह कहां है? उसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है ? मैं यही बता रहा हूं कि उसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है । सारे फाइनेंस और ट्रांज़ैक्शन का वह इंचार्ज था । जब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक आपको घोटाले की तह में जाने का मौका नहीं मिलेगा, आप जा नहीं पाएंगे । मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : ध्यान आकर्षित मत कीजिए, क्लैरिफिकेशन मांगिए ।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, *तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए । *वह पर्सन है जो इस घोटाले का एक सूत्रधार है । मैं मंत्री महोदय को होम ट्रेड कंपनी के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आपको जानकारी नहीं देनी है, आपको सिर्फ क्लैरीफिकेशन मांगना है, आप सवाल पूछिए ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): मंत्री महोदय के पास जानकारी है ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए । आपके पास जानकारी है या नहीं है ?

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं क्लैरिफिकेशन ही दे रहा हूं ।

श्री सभापति : आप क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, आप सवाल पूछिए ।

श्री संजय निरुपम : अगर यह तय हुआ है कि मुझो बोलने नहीं दिया जाएगा तो ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : यह गलत बात है, आपको बोलने दिया जा रहा है ।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, इतना गंभीर प्रश्न है, इतना बड़ा घोटाला है ।

MR. CHAIRMAN: It is not a general debate. You have to seek clarifications, not give suggestions.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जो क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं वह यह है कि होम ट्रेड कंपनी के बारे में इनके पास कितनी जानकारी है ? होम ट्रेड कंपनी के तीन में से एक डायरेक्टर श्री संजय अग्रवाल, कभी लॉयड सिक्योरिटी के सी.ई.ओ. हुआ करते थे। उस लॉयड सिक्योरिटी, लॉयड ब्रोक्रेज फर्म को 1997 में बैंकरप्टसी की वजह से और कुछ गलत ट्रांजेक्शन की वजह से सेबी ने बैन कर दिया था लेकिन बाद में उसी व्यक्ति को दूसरी कंपनी शुरू करने की परमिशन दी जाती है । इसमें मॉरीशियस बेस्ड ओ.सी.बी. भी इन्वोल्व्ड है । हम बार-बार ओ.सी.बी. के बारे में बोलते रहते हैं इसलिए मैंने पूछा है कि पैसा कहां गया । मुझो डर है, आशंका है कि कहीं हमारे कॉ-ऑपरेटिव बैंक्स का पैसा मॉरीशियस बेस्ड जो ई.डी.टी.वी. है, उस कंपनी के माध्यम से बाहर तो नहीं चला गया है । यह छानबीन महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर सकती, यह छानबीन नागपुर के छोटे-मोटे कांस्टेबल और इंस्पेक्टर नहीं कर सकते हैं । इसकी छानबीन के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए । शेयर स्कैम को समझाने वाले जो सी.बी.आई. के लोग हैं उनके हवाले इसे करना पड़ेगा ।

श्री सभापति : आप सजेशन्स दे रहे हैं, आप क्लैरिफिकेशन्स पूछिए ।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी सीमेंस प्रोविडेंट फंड का जो प्रश्न आया है, जिसका टोटल डिपोजिट चार सौ करोड़ के आस पास था, उसमें 1992 या 1994 में ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You have spoken for 22 minutes...*(Interruptions)*...

श्री संजय निरुपम : सर, 22 में से दस मिनट तो इधर ले लिए गए हैं ।

श्री सभापति : नहीं, यह बात नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Now, you should wind up...*(Interruptions)*...You have to only seek clarifications, because Calling Attention Motion is not a debate.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता : सभापति जी, दस-दस मिनट का टाइम सभी को मिलना चाहिए क्योंकि ये बीस मिनट बोल चुके हैं ।

MR. CHAIRMAN: Moreover, each Member should take five minutes for seeking clarifications so that the Minister can also respond to those clarifications.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मुझे ऐसी जानकारी है कि प्रोविडेंट फंड में जो हमारी बचत है, हमारे पैसे हैं उन पैसों का दुरुपयोग या उपयोग शेयर मार्किट या डेब्ट मार्किट में हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है । लेकिन इसकी आज तक कोई छानबीन नहीं हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रोविडेंट फंड के पोर्टफोलियोज का कहां-कहां इन्वेस्ट हुआ है ? मंत्री जी इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लेकर आएं, इसके बारे में बताएं कि प्रोविडेंट फंड का पैसा कहां-कहां है ? जैसे कि सीमेंस में लगभग 92, 94 करोड़ रुपये डूब गए हैं जबकि इसमें टोटल डिपोजिट ही चार सौ करोड़ का था और उसका पच्चीस प्रतिशत टोटल डिपोजिट खत्म हो गया, बिल्कुल उसी तरह से अलग-अलग संस्थाओं के प्रोविडेंट फंड के पैसे भी डूब रहे हैं । जिस दिन अलग-अलग संस्थाओं के पैसे डूब जाएंगे उस दिन हा-हाकार मच जाएगा । जिस तरह से यू.टी.आई. स्कैम था उससे भी बड़ा घोटाला पी.एफ. का स्कैम हो सकता है । मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना पड़ेगा । प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है वह फिर से रीडिफाइन करनी पड़ेगी, उसे नए तरीके से समझना पड़ेगा तब कहीं जाकर प्रोविडेंट फंड, जो अभी तक लग रहा था कि अछूता है, उसे बचाया जा सकता है । चलते-चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा,... क्लैरिफिकेशन ही है सभापति जी कि मुम्बई कॉ-ऑपरेटिव बैंक के बारे में मैं जो इतने दर्द के साथ कह रहा हूं उसका परपज, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ...(व्यवधान)... एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुम्बई कॉ-ऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आरोप है, ऐसा शक है, मैं बाकायदा शक की एक कॉपी आपको दे रहा हूं कि उस बैंक के जरिए जाली नोटों का धंधा हो रहा है । मुम्बई के छोटे-छोटे कॉ-ऑपरेटिव बैंक्स वाले जब शाम को बीस-पच्चीस लाख रुपये निकालते हैं तो उसमें अक्सर दस-पंद्रह हजार के जाली नॉट दिए जाते हैं । इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, इसकी मैं मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं । जब तक इस मामले की छानबीन नहीं होगी तब तक मुम्बई कॉ-ऑपरेटिव बैंक को बचाया नहीं जा सकता है । धन्यवाद ।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, at the outset, I am somewhat disappointed by the statement because it does not really capture the complexity and the wide ramifications of the scam. There is no doubt that there is a scam. That has been admitted in the statement itself. But we had seen this approach of the Government earlier in the share market scam also. In paragraph 4 on page 2, the opening line is, "There has been no failure on the part of the regulators, as alleged". I would like to ask the hon. Finance Minister, through you, Sir, whether it was not a fact that Mr. Sanjay Aggarwal, the CEO of M/s Home Trade Ltd., of which there was a mention in the statement, was the CEO of M/s Lloyds Brokerage in 1997. Was it not a fact that on 16th January, 1997, there was a major fluctuation and oscillation in the share prices, and the SEBI had found that M/s Lloyds Brokerage was guilty of rigging share prices? It was under inquiry. While

the inquiry was going on, was it not a fact that a Mauritius-based company called EDTV purchased M/s Lloyds Brokerage, and, that too, for a pittance, at Rs.1.50 per share. Then, was it not a fact that while the inquiry was on, M/s Lloyds Brokerage was allowed to be renamed as M/s Euro-Asian Securities, and subsequently, a change in the management of M/s Lloyds Brokerage, now rechristened as M/s Euro-Asian Securities, was allowed? We know that while an inquiry is going on, the regulator should freeze the activities of that company, including the name it carries and the management it has. Now, this is my first question: how can we give a clean chit to the regulator? Then, the second question is this. Now, it is a fact that when, in the earlier share market scam the involvement of the Madhavpura Cooperative Bank came to light, and there were grave violations and criminal acts committed by the Madhavpura Mercantile Cooperative Bank, the RBI came out with a guideline that, as a matter of safety-net, all cooperative banks should invest at least 25% in Government securities. I want to know whether it is a fact that the cooperative banks, at that point of time, were proficient in dealing in Government securities, which is a specialised business. I want to know whether the RBI had put in place certain transparent and technologically upgraded systems, whereby any foul-play could be restricted. I want to ask the hon. Finance Minister whether it is not a fact that the NABARD has to look after all these rural cooperative banks. The SIDBI has to supervise the State Financial Corporations. The National Housing Bank has to monitor and regulate the housing finance companies. The total number of State cooperative banks in the country is 29. There are 367 district central cooperative banks, 804 agricultural societies and 196 regional rural banks. Thus, the NABARD has the wherewithal to properly supervise and regulate all these banks. My third question is, when the Cooperative Banks were allowed to invest to the tune of 25 per cent of their investment in guilts, with the kind of inexperience which the District and Cooperative Banks were having, they had to fall back on certain brokers, in many cases, which were, as per the RBI guidelines, not listed in BSE or NSE. Therefore, what we see now is that, this company, Home Trade, went for purchase of G-secs of a shorter time-period, seven-eight months maturity, where there is an irregular kind of delivery system in vogue, at present, for this kind of securities; without taking the physical deliveries, they are giving only photocopies of the securities. The guilts they are purchasing, they are again reselling it to different banks, this is how about 20 Cooperative Banks got involved in the scam. This was possible only because the kind of regulatory oversight and

the kind of system that is there is completely inadequate to deal with the situation.

Sir, my fourth question is, there has been a very strong demand from market players and sections of the Government; there are murmurs and whispers that the Provident Fund money should be allowed to be invested in the share market in order to provide liquidity to the market. What is the situation here? A retired IRS officer who was the Chief Executive of Seimens Provident Fund; Rs. 94 crores have gone, and almost openly he was doing this through Sanjay Agarwal. His wife was having two investment companies, and that money has gone there. The total amount of money involved, including the cases of cooperatives which have come to light so far, is about a thousand crore. Where has the money gone? The statement of the Minister has not thrown any light on this. The Minister has to explain it because this thing has been going on for the last one month. It is very clear; it is also connected with the market situation because, instead of investing the money, which they were getting from the Cooperative Banks or the Provident Fund, in debt instruments, these moneys were being invested in equity instruments; and when the share market crashed, they could not recover that money. Therefore, all the money that they took in lieu of securities, which they never delivered, was channelled elsewhere. Where has the money gone? The Minister's statement does not say anything on where the money has gone. Who is to find it out? The Government is the executing agency. I am not interested which party and which person is involved in it. But, after the Harshad Mehta Scam, when we were discussing the share market scam two years back here, in this House, and for the last more than a year, in the JPC, we were under the impression that Government securities, as an instrument of scam, were not there. We have been told by the RBI that the situation has been corrected. Where are the regulators? Now, you see huge, fraudulent, play of Government securities in this entire scam. Therefore, Sir, it is a very, very serious and sad situation in the country. What I understand is, some Urban Cooperative Banks were already involved in the earlier share market scam. The Joint Parliamentary Committee is going into that. So, the whole matter should be referred to the JPC, by expanding its terms of reference. It should be brought under the purview of the Joint Parliamentary Committee. Will the hon. Finance Minister agree to it?

I think, the financial sector of the country is in the doldrums. We are going in for new instruments. But we have not put in place proper

regulators, a proper system, a proper technology, a transparent system, and it is anybody's business to loot the money of the small depositors. What is the security for the money of the small depositors in this country, who deposit their savings in the Provident Fund, earned through their blood and sweat? It is the workers' money. It is the small people's money. Can it be just allowed to be looted and plundered by these unscrupulous operators, with the regulatory supervision remaining absent? On the top of it, the Finance Minister gives them a certificate that there is no failure on the part of the regulators, as alleged, nothing could be more unfortunate for this country and for this nation.

Thank you.

SHRI NARENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, many points have been raised. Issues have been raised and clarifications have been sought. I will not repeat them. But it is very difficult for me to share the perception that there has been no failure on the part of the regulators as alleged. Very difficult. Reasons for this are simple. Is it not a fact that cooperative banks, for the last couple of years are colluding with high-profile brokers in Mumbai? They are not following the guidelines and the rules of governance framed by the RBI. I would like to read from the Annual Report, 2000-01, of the RBI. It is on page 13. It says, "The existing supervisory system for urban cooperative banks allow for regulatory arbiters and potential for contagion effects. Furthermore, the existence of overlapping jurisdiction between the Central Government, the State Government and the RBI hinders the speed of response of unforeseen development." Mark the words, 'unforeseen development.' These are unforeseen developments.

I would, through you, like to know from the Minister, for how many years more these unforeseen developments will continue? I know, the Government of India can do very little. Mr. Chairman, Sir, the reason is cooperatives is more a State-subject, and this overlapping jurisdiction is creating a lot of confusion.

Sir, the Reserve Bank of India, in the same Report, under heading, "Monetory and credit policy statement." The RBI has mooted a proposal to stop all this. "The RBI has mooted a proposal for setting up of a new apex supervisory body, which can take over the entire inspection, supervisory function, in relation to the scheduled and the non-scheduled urban cooperative banks. The apex body could be under the control of a separate high-level supervisory board consisting of representatives of the Central

Government, the State Government, the Reserve Bank of India, as well as experts." Will the Minister accept that such a body is needed? And, if such a body is needed, why is the Government of India feeling hesitant to follow the advice of the RBI in this matter? This is my second query.

Mr. Chairman, Sir, the issue is so important that the poor administration and the poor governance of regulations of these banks has become a continuous process, more or less. We know about the Harshad Mehta case and the Madhavpura Cooperative Bank case. And there was another case in Hyderabad. The Madhepura Co-operative Bank financed a bull. The money of a co-operative bank in Hyderabad was diverted to the real estate and the whole bank collapsed. A co-operative bank in Rajkot gave carte-blanche to a broker to trade in Government bonds and other bonds which, ultimately, flopped. All these things are happening. Sir, with your permission, I quote from the editorial of the *Business Standard*, which says, "Historically, most of the co-operative capital in the country has come from the Government. When the co-operatives run short of capital, the Governments give them loans and these are never recovered." Is it a fact? Has any enquiry been made? Whether it is Government's money or labourers' money or farmers' money. The money in the co-operative banks is causing a great anxiety to the investors.

MR. CHAIRMAN: Please finish it, so that other Members can also participate in the discussion.

SHRI NARENDRA MOHAN: Sir, you have been very kind to give other Members twenty-five minutes each and fifteen minutes each. So, at least, give me seven or eight minutes.

MR. CHAIRMAN: You have taken eight minutes.

SHRI NARENDRA MOHAN: No, Sir. I have taken only four minutes. I have been observing the clock. So, if you give me some more time, I shall be obliged to you.

The second query I wish to know from the hon. Minister is whether the Government is willing to handover this matter to the CBI for inquiry? If 'not', what are the reasons for it? Sir, further, I wish to know from the hon. Minister whether the Joint Parliamentary Committee, which is already probing into the Securities Scam, can also do this job more efficiently. If it is so, what is the difficulty in handing over this matter to the Joint Parliamentary Committee probing the Securities Scam? All these matters

need our total attention. The fact remains, the preventive measures, which have been taken up till now by the regulatory authorities, have not yielded any results. When the preventive measures are not yielding any results, what new policy, what new initiative the Government of India have in mind or the Reserve Bank of India has in mind? Unless new initiatives are taken, the money, which is with our co-operative banks will not be safe. It is my submission. I request the hon. Minister to please enlighten this House how long this will continue? This is a very important subject, because money belonging to millions and millions of people is involved; and scams after scams are taking place in the country. I am not blaming any political party -- either this party or that party. It is happening more in Maharashtra. It is correct. Why is it happening more in Maharashtra? This point has to be probed. Why are the co operative banks in Maharashtra facing problems? Why are Mumbai share brokers colluding with the co operative banks? More or less, the issue is more related to the Government of Maharashtra. I think, my friend, Mr. Praful Patel, should not take offence to it. But the issue is, these scams are taking place mostly in the territory of Maharashtra. And, mostly politicians have engineered them. I will not blame any political party. Why only politicians? Because they are in the co operative banks. It is they, who should to be restrained. It is they, who should be told, 'please follow the law.' Sir, I met the Governor of the Reserve Bank of India on this very issue. The RBI is very clear that unless the multiplicity of governance, unless the multiplicity of regulation is checked, it is very difficult for them to really devise a method which can stop such scams. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Mr. Gavai. Each Member should restrict himself to five minutes. There are about eight or ten Members to speak. Then, we have the Legislative Business. At 4 o'clock we have a Short Duration Discussion on the drinking water problem. So, unless we limit ourselves, we will not be able to complete our business today.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Okay, Sir. I will take just four minutes. I would like to point out the tendency on the part of the cooperative movement, the political character of the social workers -- maybe, political workers -- and the manner in which they behave. I know about the structure of all these banks because I belong to Maharashtra. I do not level any allegations against any political party. The composition of these banks -- as incorporated in the statement made by the hon. Finance Minister -- show that workers of many political parties participate in them. My pertinent point is this: With due respect, I differ with the statement of

the hon. Finance Minister. Whatever guidelines that have been given by the Reserve Bank of India are not being followed strictly. Whatever has happened in Maharashtra or Mumbai or in any other part of the country is a matter of grave concern. Unfortunately, Harshad Mehta belonged to Mumbai. But the tendency does not belong to Mumbai. The UTI scandal had spread throughout the country. It had no limits. It crossed the borders of Maharashtra...*(Interruptions)*...

SHRI NARENDRA MOHAN: Sir, I said that most of these cooperative banks are in Maharashtra.

श्री आर.एस. गवई : नरेन्द्र मोहन जी, मैं कभी टोका-टाकी नहीं करता हूं । मैं तो प्लेन बोल रहा हूं, मुझको सब मालूम है, लेकिन मैं फिर भी वह नहीं बोलता हूं । मेरा कहना यह है कि यह जो स्कैम है, इस पर हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए ।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में कोआपरेटिव मूवमेंट फली-फूली और मेरे लिए यह दैव दुर्विलास है कि महाराष्ट्र में ही यह स्कैम हो रहा है । यह जो कोआपरेटिव में स्कैम हुआ है, पहले जैसा हुआ है। मेरी सबसे ज्यादा चिंता, चेयरमैन साहब, यह है कि इस बैंक में जो इन्वेस्टर है, वह फारमर है, काश्तकार है, मजदूर है और इन्होंने अपनी सेविंग के पैसे वहां डिपॉज़िट किए हैं । What is the fate of these poor investors who are largely farmers, poor working people? What are the remedial measures?

वे तो पैसे खाकर चले गए, हजार करोड़, दो सौ करोड़ और जिन्होंने यह स्कैम किया है वे जेल में जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका क्या होगा ? सभापति महोदय, जैसा कि निवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें है कि उसका जांच कार्य शुरू है। मैंने पहले बताया कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की जो गाइडलांइस हैं, वह जांच कार्य उसके मुताबिक होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने पूरी स्टेटमैंट पढ़ी है । इस बैंक में जो गरीब काश्तकार, किसान और मजदूरों के जो डिपॉज़िट थे, उनको उनका पैसा कुछ मात्रा में वापिस करने के लिए आप क्या करेंगे ताकि सहकारी मूवमेंट बदनाम न हो ? जिस संस्था के बारे में गरीब लोगों का, काश्तकारों का प्यार था, उसके बारे में अभी दिन-प्रतिदिन उनके मन में नफरत बढ़ रही है ।

ज्यादा तकरीर न करते हुए, उसमें किसी पोलिटिकल पार्टी का इन्वाल्वमेंट बताकर उसको पोलिटिकल डिसीज़न न बताते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन छोटे-छोटे गरीब काश्तकारों और मज़दूरों आदि के जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए थे, मैं आपकी तरफ से यह अपेक्षा करता हूं कि आप उनको वह वापिस करेंगे ।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is 1 o' clock now. Do you want to skip the lunch and continue with this discussion?

1.00 p.m.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir, we can skip the lunch.

श्री प्रेमचन्द गुप्ता (बिहार): सभापति महोदय, कोऑपरेटिव बैंकों का जो स्कैम है, यह कोई छोटा-मोटा इश्यू नहीं है । यह महाराष्ट्र या दिल्ली या गुजरात के किसी एक बैंक का सवाल नहीं है । अगर यह मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो इसमें किसी तरह का बचाव नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, पूरे देश में 2,084 कोऑपरेटिव बैंक हैं और इनके पास 71,701 करोड़ रुपए के डिपाज़िट्स हैं और इन्होंने 45,856 करोड़ रुपए के ऐडवांस दे रखे हैं । इनकी NPA 14 परसेंट से लेकर 22 परसेंट तक है । जब NPA की फिगर्स सामने आती हैं, तब पता लगता है कि ये रिकवरेबल नहीं हैं । इनमें ज्यादातर पैसा ऐसा है जो डूब चुका है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है । जब FCI का जिक्र आता है तो हम सब नर्वस हो जाते हैं कि क्या है, क्या नहीं है । मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे गोडाउन में इतना सामान पड़ा है और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है ।

महोदय, यह जो कोऑपरेटिव बैंकों का इश्यू है, इसमें एक चीज समझने की है कि कोऑपरेटिव बैंकों पर किसी का कंट्रोल नहीं है । न RBI इन्हें कंट्रोल करने के लिए तैयार है और न ही स्टेट कोऑपरेटिव्ज़ रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं । स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनकी वही कहानी है कि 5 पांडवों की एक पत्नी । पत्नी एक है और उसके पांच पति हैं । आप देखिए कि कैसे छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स को ट्रैप-इन किया जाता है । एक-दो परसेंट एक्स्ट्रा इंट्रस्ट ऑफर कर दिया जाता है और छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स की पूरी जिंदगी की कमाई उन बैंकों में जमा करवा दी जाती है । इनका जो ट्रस्ट या बोर्ड होता है, वह वही होता है जो 90 परसेंट बौरोअर होता है । वह 100 रुपए में से 90 रुपए बौरो करता है । वही उसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है या बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर होता है । यह इश्यू पहले भी कई बार आया है लेकिन इस इश्यू को कभी भी सीरियसली नहीं देखा गया है ।

महोदय, मैं एक रिपोर्ट को रेफर कर रहा हूं जो इकनॉमिक टाइम्स में 11 अप्रैल, 2001 को छपी थी । इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिन्हें मैं हाऊस के सामने रखना चाहता हूं ताकि वित्त मंत्री इन्हें देख सकें । महोदय, इस तरह के 262 वीक बैंक हैं, 17 बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए गए और इनकी कन्फर्म NPA 4,534 करोड़ रुपए है । इन कोऑपरेटिव बैंकों में इन्वैस्टर्स का जो पैसा होता है, उसको या तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाता है या फिर गोल्ड में लगा दिया जाता है या फिर सिर्फ पेपर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिया जाता है या फिर प्रॉपर्टीज में लगा दिया जाता है । अगर मार्केट ठीक चल जाता है तो उसकी पेमेंट ठीक होती रहती है । जिस रोज मार्केट में कुछ ऊपर-नीचे हो गया, उस दिन वह सारा पैसा डूब जाता है । किसी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है । इस सारे मामले में RBI के जो अधिकारी हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों के अधिकारी हैं, जो ट्रस्ट हैं, ये सब लोग मिले होते हैं । बगैर इनकी मिलीभगत के यह काम नहीं हो सकता है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को कुछ वैस्टेड इंट्रस्ट के हाथ में देकर इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की

इज़ाज़त दी जाएगी ? आप इसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि फर्म एकाउंटेबिलिटी हो जाए और अगर उस एकाउंटेबिलिटी के बाद कुछ होता है, तो उसके लिए कानून में जो भी प्रावधान हैं, उनके मुताबिक कार्यवाही की जाए ।

मान्यवर, इस बारे में एक कमेटी बनी थी श्री.के.माधवराव कमेटी और उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए RBI को कुछ रिकमंडेशंस दी थीं ।

जिसमें दिया गया कैपिटल एडीक्वेसी रेश्यो, टाइटनिंग आफ ब्रांच लाइसेंसिंग पालिसी, रि-डिफाइनिंग वीक बैंक पालिसी, इन सब चीजों के संबंध में उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण सजेशन्स दिए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कुछ किया गया है? क्या वित्त मंत्री महोदय कोई ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि यह जो लूट-खसोट है, इसके लिए किसी की एकाउंटेबिलिटी रख दी जाए और उनको सख्त से सख्त दंड दिया जा सके? जब तक एक्जेम्पलरी पनिशमेंट किसी को नहीं दी जायेगी, तब तक यह चालू रहेगा और करोड़ों लोग इसमें पिसते रहेंगे। धन्यवाद ।

श्री प्रफुल्ल पटेल : सभापति महोदय, हमारे राज्य की बात है और कोआपरेटिव बैंक के संबंध में एक गंभीर प्रश्न का निर्माण हुआ है। मैं संजय निरुपम जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने आज इस कालिंग अटेंशन के जरिए से सदन का ध्यान इस बारे में आकर्षित किया है।

सभापति महोदय, अभी प्रेमचन्द गुप्ता जी ने कुछ आंकड़ें यहां पर बताये कि देश में कोआपरेटिव बैंकों में कितने हजार करोड़ रुपये जमा हुये हैं। महाराष्ट्र और कई राज्य ऐसे हैं, यू.पी. है, कर्णाटक है, गुजरात है, जहां पर कोआपरेटिव क्षेत्र बहुत ही ताकतवर क्षेत्र बन चुका है।'आमतौर पर कोई भी व्यक्ति पहला अगर डिपोजिट करने के बारे में सोचता है तो वह कोआपरेटिव क्षेत्र में सोचता है। यह बात सही है कि कोआपरेटिव क्षेत्र में नियन्त्रण कम होने की वजह से डिसक्रिशन ज्यादा है, उस डिसक्रिशन की वजह से ज्यादा ब्याज दिया जाता है, थोड़ा डिपोजिट हो जाता है, डिपोजिटर की जो कंडीशन्स होती हैं, उसमें लचीलापन ज्यादा होता है और इस वजह से इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन अभी मुम्बई में, महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में गुजरात में, कोआपरेटिव बैंकों में हुए घोटाले के बारे में जो चर्चा हो रही है, यह घोटाला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसमें करीब 80 करोड़ रुपया गुजरात की सात कोआपरेटिव बैंकों का भी इन्वाल्व है। इसके अलावा सीयेंस का 100 करोड़ रुपया प्रावीडेंट फंड का है, वह भी इसमें शामिल है। मैं इस बात को मानता हूं जो संजय निरुपम जी ने यहां पर कही कि यह घोटाला यहां तक ही सीमित नहीं है, निश्चित रूप से इसके कहीं और गहरे इनरोड्स हुए होंगे और यह घोटाला 500 करोड़ रुपये क्या, हजार करोड़ रुपये तक भी हो सकता है। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यहां पर कुछ बातें कहीं हैं, नाबार्ड का इन्सपैक्शन हुआ, नाबार्ड के इन्सपैक्शन के पश्चात आर.बी.आई का इन्सपेक्शन हुआ और उसके बाद यह बात सामने आई। उसके पश्चात स्टेट गवर्नमेंट ने और आर.बी.आई ने मिलकर कुछ कदम उठाये हैं। लेकिन एक बात पर मंत्री महोदय आपको जरूर ध्यान देना होगा कि आज कोआपरेटिव सैक्टर के ऊपर, विशेषकर के कोआपरेटिव बैंक, क्योंकि हम जे.पी.सी में भी देख रहे हैं कि माधेपुरा का एपिसोड हुआ और भी कोआपरेटिव बैंक का हुआ। हम लोगों के पास इसके बारे में कोई सही रेगुलेशन नहीं है। आप आर.बी.आई की तरफ से रेगुलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कहते हैं कि यह स्टेट

गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होने के नाते वहां पर जिस प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए, वह हो नहीं पाता है। यह महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, हर स्टेट में इस तरह की प्राब्लम आई हैं। मुझे जानकारी है कि कुछ दिनों पूर्व आर.बी.आई की तरफ से कोआपरेटिव बैंक और कोआपरेटिव सैक्टर को रेगुलेट करने के लिए कुछ सुझाव आपके मंत्रालय को दिये गये हैं। उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि जैसे एक डिप्टी गवर्नर बैंकिंग सैक्टर को देखा करते हैं, वैसे ही एक गवर्नर की पोस्ट क्रिएट करके कोआपरेटिव सैक्टर को भी इसके दायरे में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा-बहुत इनेक्टमेंट करने की भी आवश्यकता पड़े तो आप यहां पर पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट करिए। जिससे कि ये कोआपरेटिव बैंकिंग सैक्टर आपके नियन्त्रण के दायरे में लाया जा सके। ऐसा करने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता है, क्योंकि दिन प्रति दिन इस प्रकार के घोटाले हमारे सामने आते जायेंगे और हम लाचारी में सिर्फ यहां पर चर्चा करते रहेंगे।

यह बात सही है कि आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में आपके पास कुछ हद तक रैगूलेशन है क्योंकि परमिशन जो है - आज अगर कोऑपरेटिव बैंक शुरू करना होता है तो वह स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं है, वह आर.बी.आई. के अधिकार में है । जब आर.बी.आई. परमिशन देता है, तब कोऑपरेटिव बैंक शुरू किया जाता है । जब आप परमिशन देते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस को स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है । क्योंकि मुझे जो जानकारी है, आम तौर पर कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड में बहुत प्रोफैनलिज्म होता नहीं है, आम तौर पर लोकल लैवल पर जो ऐक्टीविस्ट होते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सोशल वर्कर हो, बिजनेसमेन हो, ट्रेडर हो, इस प्रकार के लोग कोऑपरेटिव बैंक के प्रोमोटर बनते हैं । उसके साथ साथ आपकी तरफ से, मुझे जानकारी है कि एक क्लास वन ऑफिसर, यानी कोई नेशनलाइज़ बैंक का ब्रांच मैनेजर रहा हुआ आदमी, उस लैवल का आदमी, मैक्सिमम उस लैवल का अगर कोई आदमी होता है तो उसे उस बैंक के एम.डी. के तौर पर रखा जाता है। अब आप सोचिए कि जिन बैंकों में हजारों करोड़ रुपये का बिजिनेस होने वाला हो, वहां पर एक ऑर्डीनरी ब्रांच मैनेजर रहे हुए आदमी को अगर आप एम.डी. की पोस्ट देते हैं तो उसको सिक्योरिटीज़ की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी क्योंकि यह एक कॉम्पलैक्स बिजिनेस है । मैं यद्यपि बिजिनेस बैकग्राउंड का हूं., फिर भी मुझे अगर कोई सिक्योरिटीज़ के बारे में बहुत ज्यादा बात करे तो एक बेसिक नॉलेज के अलावा मुझे भी जानकारी नहीं है । इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है, या जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है, उसके बारे में ज्यादा स्ट्रिजेंट कंडीशंस डालें, वरना इस प्रकार के लोगों को अगर हम मौका देंगे तो आगे आने वाले दिनों में ये स्कैम्स के प्रमाण बढ़ते जाएंगे और लाचारी के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं होगा । इसलिए कृप्या इस बारे में आप सोचिए । महोदय, महाराष्ट्र के बैंकों के बारे में यहां पर कुछ कहा गया, इसलिए मुझे इस संबंध में थोड़ा क्लैरीफिकेशन देने के लिए सभापति महोदय आपको मौका देना चाहिए । यद्यपि यह विषय से हटकर है लेकिन हमारे ऊपर कुछ आरोप यहां पर लगाए गये हैं । मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्योरिटीज का स्कैम होने के बाद जैसे ही इस बात की जानकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी गयी, तुरंत वहां पर एफ.आई.आर. लॉज हुई और एफ.आई.आर. लॉज करने के बाद वहां पर तुरंत सुनील केदार या जो भी व्यक्ति इसमें इनवॉल्व थे, उन पर तुरंत कार्यवाही की गयी, उनके बोर्ड डिजॉल्व करने में आए। उसके साथ साथ वहां पर उनको अरैस्ट करने का काम किया गया ।

श्री संजय निरुपम : यहां पर सबसे बड़ा रोल है, क्या आपको मालूम है ? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन* थे, उसके बाद * थे और * ने सारा घोटाला किया है । आप क्या ऐक्शन लेने जा रहे हैं ? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का इसमें ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : एक सुनील केदार जैसे छोटे आदमी के खिलाफ ऐक्शन लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं ? ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL: Where is the issue of Maharashtra State Cooperative Bank. यहां महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ईशू ही नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : इनके ऊपर ऐक्शन लीजिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप कुछ भी बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे । ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : आप इनके खिलाफ ऐक्शन लीजिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति महोदय, अगर इस प्रकार की बातें होंगी, ...**(व्यवधान)**...यहां पर आप और कुछ नहीं करते । ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: The names of those persons who are not present here should not be taken

SHRI PRAFUL PATEL: This should be expunged.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, यह हाउस को मिसगाईड किया जा रहा है । मैं बताना चाह रहा था कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एक्स चेयरमैन * के इशारे पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है । उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL: No; no, it is not like that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The names of the persons who are not present here should not be mentioned. ...*(Interruptions)*... Those names should not come on record.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय निरुपम : * उनके ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, it should be off the record.

MR. CHAIRMAN: Yes;

SHRI PRAFUL PATEL: It should be expunged.

MR. CHAIRMAN: I shall look into it.

श्री प्रफुल्ल पटेल : अगर इस प्रकार की बातें यहां पर हो रही हैं । हम खुद चाहते हैं कि यह जो घोटाला हुआ है, इसकी गहराई में जाना आवश्यक है । ये महाराष्ट्र पुलिस की बात करते हैं । महाराष्ट्र पुलिस ने जो प्राथमिक काम करना था, वह किया है, सी.आई.डी. को काम दिया है । अगर संजय निरुपम जी सी.बी.आई. को इसे देने की बात करते हैं और आपको आवश्यक लगता है तो आप इसके बारे में कहिए । इसमें किसी को प्रोटैक्ट करने या बचाने की बात नहीं है ।...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : जब तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं होगी, सी.बी.आई. की इन्क्वायरी नहीं हो सकती । ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL : Let the request come from the Finance Minister that there is an issue which needs to be probed further, and this matter should be handed over to the CBI. I am sure, the Maharashtra Government can consider these things. We also, as Members of Parliament, belonging to Maharashtra, would like to go into the details and the depth of it. And, we will also recommend to our Government, we will also prevail upon our Government that 'yes, the matter should be handed over to the CBI.' लेकिन जहां तक इस प्रकार की बात होती है और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से राजनैतिक भेदभाव करते हुए यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि सतगुरु जंगली महाराज कोऑपरेटिव बैंक भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से भरा हुआ है, उसमें 80 करोड़ रुपया गुजरात के बैंकों का इनवॉल्व हुआ है । गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है, वहां पर आपके समर्थक बैठे हुए हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, आपके द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं, उनके नाम नहीं लिए जाएंगे । ...**(व्यवधान)**...आप यह व्यवस्था दे चुके हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : उन्होंने आरोप लगाया है, मैंने आरोप नहीं लगाया है । मैं तो सिर्फ डिफेंड करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया । यहां पर

---

* Expunged as ordered by the Chair.

इन्होंने * नाम लिया, * नाम लिया, they are not present here. How are they supposed to defend themselves. They are the persons belonging to our party and we being a representative of the party...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : वे नाम तो एक्सपंज करा दिए हैं । ...**(व्यवधान)**... वे नाम तो एक्सपंज हो गए हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : एक्सपंज से क्या मतलब है ? जंगली महाराज कोऑपरेटिव बैंक में सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, आप क्यों रोक रहे हैं ? किसने कहा कि जंगली महाराज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए ? उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए चाहे वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हो लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों बचाया जाना चाहिए, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: *Please, let him continue.*

श्री प्रफुल्ल पटेल : महाराष्ट्र में हमारी पार्टी की हुकूमत होने के बाद भी सुनील केदार को वहां पर अरेस्ट किया गया है । ये आरोप, ये सारी बातें ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन : यह बात बेबुनियाद है, महोदय, आप इसको एक्सपंज कराइए । ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Only Mr. Praful Patel will speak. Nobody else will speak. Mr. Patel, you kindly wind up now.

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : सर, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है । संजय निरुपम जी की आदत है, इस प्रकार से वे 22 मिनट ले लेते हैं । जान-बूझकर sensalisation करने की उनकी आदत है ।

श्री सभापति : अब आपको 22 मिनट नहीं लेने हैं ।

श्री संजय निरुपम : इसमें sensalisation की क्या बात है ? सभापति जी, मेरे पास इनफॉर्मेशन है तो उसे सदन में रखने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं । मैं अपनी जानकारी सदन में रखना चाहता हूं । यह मेरी आदत है इसलिए इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए । मेरे पास जो इनफॉर्मेशन थी, वह मैं सदन में रखना चाह रहा था । ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल : सर, अगर वे स्वतंत्र हैं तो हम भी स्वतंत्र हैं, हम कोई yield करने के लिए नहीं हैं । ...**(व्यवधान)**...

---

* Expunged as ordered by the Chair

श्री एकनाथ के.ठाकुर (महाराष्ट्र): प्रफुल्ल जी, मामला सीरियस है । आप भी सी.बी.आई. इनक्वायरी की मांग करें, हम आपसे विनती करते हैं । आप मांग कीजिए ।

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप तो स्कूल ऑफ बैंकिंग चलाते हैं, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर को बताइए ।

श्री एकनाथ के.ठाकुर : आप सी.बी.आई. इनक्वायरी की मांग कीजिए, यही हमारी विनती है ।

श्री प्रफुल्ल पटेल : हमने मांग की है । सर, माननीय सदस्य स्कूल ऑफ बैंकिंग चलाते हैं। उनको तो फाइनेंस मिनिस्टर को बताना चाहिए कि इस प्रकार के घोटाले कैसे रोके जाएं । ...**(व्यवधान)**...

श्री एकनाथ के.ठाकुर : इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं ।

श्री प्रफुल्ल पटेल : सर, हमने तो सुना है कि इनको भी कोई प्रमोशन मिलने वाला है, बालासाहेब विखे पाटील जी की जगह ये बैठने वाले हैं, इनको अनुभव है, इसलिए ये ज़रा ज्यादा बोल रहे हैं और संजय निरुपम जी के लिए एक पोस्टेज स्टैम्प भी आगे निकालने वाले हैं, उनका भी कुछ न कुछ होगा ।

MR.CHAIRMAN: Please, wind up now.

श्री प्रफुल्ल पटेल : सर, मैं दो क्लेरिफिकेशन्स मांग रहा हूं । पहला यह कि इस प्रकार के कोऑपरेटिव क्षेत्र के बैंकिंग घोटाले जो बार-बार हमारे सामने आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए रिज़र्व बैंक या रेग्युलेटर की ओर से हमारे वित्त मंत्री जी कुछ concrete सजेशन्स हमारे सामने रखने की कोशिश करेंगे ? दूसरा क्लेरिफिकेशन यह है कि इस घोटाले की गहराई में जाने के लिए जिस प्रकार की भी इनवेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, उस इनवेस्टिगेशन के लिए यहां से, वित्त मंत्रालय की ओर से जो संबंधित विभाग है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे ? यह निश्चित है कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो घोटाले हमारे राज्य में हुए और विभिन्न राज्यों में हुए, इनके बारे में पूरे सदन की जो चिंता और भावना है, उसके साथ मैं अपनी भावनाओं को जोड़ता हूं । धन्यवाद ।

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, this is a very serious matter. We should not confine it to some political parties or to those who are running the cooperative banks or those who are not running the cooperative banks. More than one lakh crore of rupees of the depositors is involved in the cooperative banking sector. So, we have to take into consideration the seriousness of the issue. The question here is why it was first Harshad Mehta; later on Ketan Parekh and now it is Sanjay Agarwal? Why has this scam started? It was in October 2001, when the Reserve Bank of India in order to control the cooperative banks directed all the urban cooperative banks, and the cooperative banks, to invest 25 per cent of their SLR in Government securities, which was not earlier mandatory. At

that point of time, it was admitted and several representations were also made that the cooperative banks did not have the expertise to invest in Government securities because the cooperative banks were located in the district centres. Except a few banks in Maharashtra and Gujarat and some parts of Karnataka, all banks are located in urban centres. So, they were asked to invest by March, 2002. They should complete it by that date. Earlier, they were investing almost 15 per cent of the total SLR. That amounts to about Rs.1500 crores. An immediate market was created for unscrupulous brokers to find an opportunity. All of a sudden, Rs.1500 crores' investment in securities had to be found out by the urban banks because they had to invest the amount within that period. They had to find out where to buy from. They did not have the expertise. They would have to approach some brokers which was a problem. I would like to know why, before asking the urban cooperative banks to invest, the Reserve Bank should not have found out whether there is expertise with the cooperative banks and how they should invest in these Government securities. That is No.1.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair]

Secondly, here, there is a failure on the part of the SEBI also in respect of the registration of Home Trade. Despite objections, despite the involvement of one of the directors in the Lloyds Finance, the SEBI has given licence to Home Trade. This has to be probed. All of a sudden, we see so much of advertisement by Home Trade. They were doing several trades. They were using the film stars, they were using the cricket stars. So many advertisements came. Nobody knew what this Home Trade was doing. There were full-page advertisements in papers. There was nothing except 'HM'. Investments of crores and crores of rupees have been made by Home Trade. The SEBI has not taken note of such an organisation. When they were entering the stock market, when they were applying for SEBI membership, why was not the SEBI careful? Why did they give broker's licence? Every time, it is the brokers who do it.

My third point is this. Why should the urban banks be allowed to invest in shares? I would suggest, it is not the job of the urban banks to advance on shares. The cooperative sector has to serve the small man. The monies are from investors. I would like to know the background of this five per cent. Why should the urban banks invest five per cent of the total advances in the share market? Where is the need for urban banks to invest in share markets? They are located outside. They do not have the

expertise. As most of our colleagues have said, the people who form the urban banks are not experts. It is a cooperative movement. The board is never formed of experts. They may even be illiterates. The membership is open to all. Anybody can contest for directorship. There is no qualification prescribed for cooperative society membership. It is a democratic institution. The directors have to be elected from the shareholders. In that system, definitely, they will not be having the expertise. The board will not have the expertise. They will come from various sectors. So, it is very difficult for us to expect of the Board of Management to have expertise to deal with either the securities or the stock market. It is the duty of the regulator to see that the deficiencies in the system, whatever they are, are removed. The system has contributed a lot to the economic development of the country. The banks have mobilised a sum of Rs.1 lakh. If you take the central, the urban and the district cooperative banks together, they have mobilised, rightly or wrongly, a saving of more than Rs.1,50,000 crores! And it is not that all this amount has gone into scams. It has gone into productivity. The cooperative sector has contributed a lot to the economic development. What is needed today is a proper regulatory system, and also ...*(Time-bell)*... Sir, I want five minutes more. Despite all its defects, the cooperative banking system has to be there. The only thing is, we have to regulate it. I would like to know from the hon. Finance Minister, what was the role of SEBI in giving a licence to M/s. Home Trade Ltd.; whether some urban banks, functioning outside Maharashtra, are also involved in the securities scam; how many regional rural banks, particularly, in the North-Eastern region, have invested in securities; whether any regional rural banks are also involved in the securities scam; and whether the cooperative banks have also invested in PSU bonds. Most of the public sector undertakings have issued bonds at a very high rate of interest. Some PSUs had issued bonds @ 16 per cent, 18 per cent, 20 per cent, and the PSUs are now in trouble. Government guarantees are given, but, still, they are not able to meet their obligations. I want to know how many crores worth of PSU bonds are involved.

I now refer to the Madhavrao Committee Report. There is a dual control system. It is said that the licence is given by the Reserve Bank of India; inspection is done by the Reserve Bank of India. The Banking Companies (Regulation) Act is administered by the Reserve Bank of India. Only a society is registered under the Registrar of Cooperative Societies. If it is a company, then, it is registered under the Registrar of Companies. Why should there be dual control? Dual control is causing a lot of trouble.

Even if the Reserve Bank of India finds certain mistakes, it is not in a position to take immediate action. It will have to write to the State Registrar, and the State Registrar cannot take immediate action. Again, he will conduct an audit. The State Audit Department and the Cooperative Department do not have any expertise to conduct audit of investment transactions of the cooperative banks. So, there will be a delay. That delay will cause a lot of embarrassment. If the Reserve Bank of India, like any other State Bank, issues a licence to a bank, whether it is in cooperative sector or in the private sector, it should be in a position to take immediate action, if such aberrations and such scams take place. If it is a private sector bank, the Reserve Bank takes immediate action. Why is the Government delaying its decision? The Reserve Bank of India has been consistently demanding that this dual control should go. The Madhavrao Committee Report is four years old. Four years back, it made the recommendation. But nothing has been done so far. The entry norms should be made more stringent. A person can form a cooperative bank with just Rs.5 crores! The entry norm has to be changed, keeping in view the experience we have had. Anybody can float an urban cooperative bank. If you want to start a bank in the private sector, you should have a Rs.200 crore capital. Here, it is only Rs.5 crores. So, the entry norms should be made very stringent. I would like to know from the hon. Minister whether this dual control will be done away with. The Reserve Bank of India is the only authority which is going to control the urban cooperative banks. I would like to know the number of cooperative banks in other States, which are inovled in this; whether it is Gujarat or any other State. The point is that many of the scams originated in Maharashtra because the Bombay Stock Exchange is there, and you are allowing the cooperatives to engage in share dealings. This problem is not in other States. But its effect will be there on the entire cooperative sector. I would like to submit that cooperative banks all over the country are under suspicion today. If the suspicion about the cooperative banks remains, no banks will be able to survive. Therefore, the Government must take a serious note of it; and take stringent and immediate action to reform the cooperative banking sector. Thank you.

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, when we discussed the UTI and other connected scams in this House, my friend, Mr. Sanjay Nirupam, burnt his fingers for stating or exposing the truth. He was put in a very embarrassing position involving his personality. There is a popular proverb in Malayalam, which says, "The fence itself eats the crop".

If the fence itself eats the crop, where is the protection? That is the case, that is the position, with all the scams. In all these scams, if we scrutinise them truthfully, we will find that the controlling agencies are also involved, including the RBI or the representatives of the RBI. Without their connivance, these scams cannot occur. This great country has become a country of scams, in the public eye. There are continuous scams. When we discussed the UTI scam, the hon. Finance Minister had promised us that some stringent action would be taken. Every deposit-mobilising institution, banking or non-banking, is controlled by some rules and regulations which originate from the Ministry of Finance. So, how can these scams go unchecked? It is not done by the Registrar of Cooperative Societies or NABARD. The brokers, the stock-exchange brokers, are also involved. The JPC is going into the UTI and other scams. I request that this scam should also be referred to the JPC. A CBI probe is all right. But the JPC should also inquire into this scam because it has been going on all these years. The Joint Parliamentary Committee should go into this scam also, and, through the evidence before it, the truth will come out as to who, at the top, are involved in this scam. If we truthfully look into all these scams, we will find that very big people are involved. That is why they are dragged on. Unfortunately, in India, when very big people are involved, the cases are dragged on. As a result, at the end, they escape from conviction. You see the record of convictions in this country. There are only a few cases. The Finance Ministry, especially the Finance Minister cannot escape the responsibility for these scams. There are rules and regulations to control these deposit mobilising banking or non-banking institutions. You had promised us in your Budget speech and while replying to the debate on the securities scam that you would control it. People are suffering. The fence is eating the crop. Millions of poor people who have trusted this Government, who have trusted us have deposited their money in these institutions. They are now suffering. I would request the Finance Minister to take some stringent actions in order to save the poor depositors.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, a lot of discussion has taken place on this issue. I wonder whether any financial year has gone without any scam taking place in this country. It has become a characteristic feature of the Indian economy. Ultimately, it is eroding the credibility of the economy which has a tremendous impact on investments. Umpteen times we have advised the Government to change the economic philosophy of the country. A socialistic economy, a mixed economy has now been thrown open to the market forces. It is a very

precarious period for the Indian economy where the Government has to act very vigilantly and regulators have to be strengthened at every stage so that the economy could not be exploited by the dacoits in this country. The entire blame can be apportioned for the rot in the cooperative movement to a vicious cycle. Excessive Government control, politically-intentioned super-session of duly elected boards, arbitrary changes in Government nominees and frequent transfers of key executives have had a crippling impact on the cooperative institutions. I do not want to go into the details of names and other things because I do not want to score any political point. Sir, one year back, I wrote a letter to the Prime Minister. I wrote this letter to the Prime Minister on 31st March, 2001. In my letter to the Prime Minister I said, "Stockbrokers, unscrupulous traders and businesspersons are exploiting these banks owing to RBI's slackness. The RBI has not learnt any lessons from the Harshad Mehta scam, which resulted in the liquidation of the Bank of Karad (BOK) and the Metropolitan Cooperative Bank (MCB). I request you to act before it is too late. All your predecessors acted on any issue only when the show was over like in the case of Harshad Mehta scam. That approach leads us nowhere because it amounts to locking the stable after the horses bolted out."

In this letter, I requested the Prime Minister to consider and implement the recommendations that have been made by the Madhavrao Committee to strengthen the cooperative system in this country; to restrict the unscrupulous elements from entering the cooperative movement and the necessary precautions that have to be taken to achieve this objective. What is happening is this cooperative movement has been used as a lever of political power. It has become a milching cow for the politicians.

Irrespective of whichever be the political party, I tell you, there are no sacred cows. Whoever gets an opportunity, they are trying to milch it. They bring the institutions under their control, without being accountable to anybody. That is the funniest aspect. Their nominees will be elected, and they will continue to rule the Board. One peculiar feature in this co-operative movement is that the persons who want to borrow money, have to become members, and these persons themselves elect their representatives. So, the borrowers themselves will become the rulers of this institution. Sir, earlier, it was that the banks served the economy of this country in a very noble manner. Now, because of lack of proper control, it has gone into the hands of unscrupulous elements like brokers. It is a new concept which has come in this system. There is no professionalism in

these co-operative institutions, and these are being plagued by politics. The politicians themselves have become perpetual rulers of these institutions. So, once a person joins a co-operative bank and becomes, say, a director, he can restrict the new entrants. This is the greatest anomaly that we have. Sir, to get a share in a co-operative bank, the existing management has to decide the allotment of shares. So, there is no possibility for new persons to get into the shareholders' list without the consent of the members of the existing Board. If I want to have a perpetual control, I will not allow others to enter as members. This is the greatest anomaly. Sir, I don't want to go into the details as to what went wrong with the system, right from Madhavpura where Rs.997 crores have been lost and never returned. The Finance Minister said that the regulators have not failed. So, who has failed? Somebody should be made accountable; the buck has to stop somewhere. Every day, it is becoming a ritual that we discuss some scam or the other in Parliament, and the Government responds saying that the regulators are not responsible for all that has happened. Ultimately, the Government is accountable to the nation. As Shri Nilotpal Basu asked, you have to tell us who is accountable to these small shareholders, these small investors, in this country. In the case of non-banking financial institutions, there is no proper regulation. I am sorry to say that these institutions are living like a woman with more than one husband. And, neither of the husbands is looking after the wife and she is becoming a destitute. That is the state of the institutions in this country. So, I would like to know from the hon. Minister, what steps the Government is contemplating to depoliticise these institutions, to induct some professionalism, and to remove this multi-institutional control. Some institutions are being controlled by NABARD; some of them are being supervised by the RBI, and some institutions are supervised by both the RBI and the State Government. And, when the RBI directs the State Government to initiate action, the Government does not take action for political reasons. This is the sorry state of affairs that is prevailing in this country. It is high time we inducted professionalism into such institutions. And, let there not be recurrence of such cases so that the country can command respect among the comity of nations. Thank you.

SHRI C. P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Sir, I have read the statement of the hon. Finance Minister. In para 4, on page 2, it is stated, "These transactions were manifestly fraudulent transactions and do not reflect in any way on adequacy of regulatory guidelines. Further scrutiny revealed absence of any investment policy as per RBI guidelines, non

existence of concurrent audit/internal inspection system, lack of trained staff and complete failure of the management, especially the board of directors, in controlling, guiding and monitoring the affairs of the bank and failure to comply with the RBI guidelines". These are the reasons that have been given in the statement. My submission is that these misappropriations are not of recent origin. This has been happening for a long time. Every time, the same kind of reasons have been attributed. Whenever there have been misappropriations in this section, it has always been alleged that there has been non-existence of concurrent audit, internal inspections, and so on, and that there has been a complete failure on the part of the management. Now, we have been facing this situation for the past fifty years. Knowing fully well that this problem has been there, what has been the Government doing all these years to curb such activities? Neither the Government, nor the RBI -- nor the SEBI now -- has been able to plug the loopholes. We all remember that in scams relating to Harshad Mehta, Ketan Parekh and the Madhopura Cooperative Bank, which involved misappropriation of more than a thousand crore of rupees, the same reasons had been advanced. Still, these misappropriations are continuing. I will request the hon'ble Minister to do something immediately to eliminate such things. My next point is this. There are these four brokers, namely, M/s Home Trade Ltd., Giltedge Management Services Ltd., Mumbai, Indramani Merchant Ltd., Kolkata, Syndicate Management Services Ltd., Ahmedabad. It is a known fact that as far as M/s Home Trade Ltd. was concerned, it staged performance; they had called Sachin Tendulkar, Hritik Roshan and Shah Rukh Khan, and had a great show. But it was the duty of the SEBI to ascertain who that person was, who was coming up so fast in the trade. This had not been taken into consideration by the main regulator. As far as the other three brokers are concerned, we do not know who they are, from where they have come and what their conduct is. It has not been looked into by the SEBI. Since these things had not been gone into, these brokers have been able to indulge in these misappropriations. Sir, as far as the Nagpur Cooperative Bank was concerned, it was directly under the control of the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India has direct control over the Nagpur Cooperative Bank. In spite of this direct control, they have not been able to detect it. Above all, one of the important things that I want to stress here is this. Who is financing these brokers? Some banking institutions must have financed these brokers and enabled them to indulge in these misappropriations. I would like to know who these banks are who have been financing these brokers. Now, we already have the recommendations

of several committees on how to plug all these loopholes, and how to remove all these obstacles. I would submit that there should be bifurcation between financial management and cooperative management. The State Governments should be vested with the power pertaining to cooperative management only. Financial management should be taken over by the Reserve Bank. Otherwise, it will be very difficult. The RBI should be vested with the powers to give directions, and if any direction is violated, it should have the power to remove the directors or to supercede the Board. The auditors should also be appointed with the consent of the RBI. If they are appointed by the cooperatives, there will never be any possibility of detection of such misappropriations. Therefore, I request the hon. Minister to immediately come out with a solution so that the cooperatives function in a better and proper manner.

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र ने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में और खास तौर से कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोऑपरेटिव बैंकों का बहुत अच्छा रोल रहा है लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित रूप से सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगता है ।

महोदय, यह जो घटना हुई है और मैंने इसका जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं इसे स्कैम नहीं मानता हूं । यह सीधा-सीधा फ्रॉड का मामला है । जो नियम और कानून RBI ने और नाबार्ड ने बनाए हुए हैं, यह उनका सीधा-सीधा उल्लंघन है । इसलिए इसकी तुलना किसी स्कैम से करने के बजाय, किसी घोटाले से करने के बजाय, अगर इसे धोखाधड़ी का मामला माना जाए तो मेरे ख्याल से यह ज्यादा उचित होगा । हमारे पास जो नियम और कानून मुहैया हैं, उनके आधार पर इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए ।

महोदय, इसमें छोटे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, गांव के लोगों का पैसा फंसा हुआ है। जब उन लोगों का पैसा एक साथ चला जाता है तो उन्हें बहुत झटका लगता है । अगर इस मामले को गहराई से देखा जाए तो पता लगता है कि सारा पैसा ब्रोकर्स के हवाले कर दिया गया और ब्रोकर्स ने मनचाहे ढंग से उस पैसे का इस्तेमाल किया और यह पैसा डूब गया। इस बारे में जो RBI की गाइडलाइंस थीं, उनको कहीं भी फौलो नहीं किया गया । अभी तो यह सिर्फ रूरल बैंकों का मामला है । अगर हमने अभी से सख्ती नहीं की तो आगे चलकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के घोटाले भी सामने आ सकते हैं । इसके बारे में माननीय सदस्यों ने प्वाइंट आऊट भी किया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी से यह कोशिश करनी चाहिए कि उनको कैसे चैक किया जा सकता है क्योंकि यह नियम है कि कोई भी बैंक एक ब्रोकर से उसके पोर्टफोलियो के 5 परसेंट से ज्यादा डील नहीं कर सकता है, उसको भी इन लोगों ने वॉयलेट किया । इसके अलावा नागपुर बैंक में तो सारी पावर चेयरमैन को दे दी गई कि जो चाहे सो करें । इस तरह से जो मनमानी हुई, उसकी वजह से ये सारे कांड हुए हैं ।

महोदय, माधवपुरा कांड के बाद यह कहा गया था कि जो SLR की जरूरत है, वह गवर्नमेंट डिपाजिट्स में होनी चाहिए, यह नहीं कि उसको दूसरे बैंक में डिपाजिट करके रखा जाए। लेकिन उसको भी फौलो नहीं किया गया ।

महोदय, बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि यह मामला JPC को दे दिया जाए। मेरे ख्याल से इस मामले को JPC को सौंपना इसे ठंडे बस्ते में डालने के बराबर होगा क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत काम है और उनको पिछला काम निपटाने के लिए करीब 2 साल चाहिए । महोदय, CBI को जांच देने की बात भी कही जा रही है । CBI को यह जांच दी जा सकती है लेकिन CBI पहले ही माधवपुरा बैंक घोटाले की जांच कर रही है । इसलिए मैं समझता हूं कि उसका सिर्फ दायरा बढ़ाया जा सकता है । अलग से जांच देने में तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ।

महोदय, इस समय देश में करीब 2 हजार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं और 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं और इनके पास लोगों के सवा लाख करोड़ रुपए जमा हैं जो कि पूरे बैंक में जमा धनराशि का 10 प्रतिशत है । इनको देखने के लिए हमने मल्टी रेगुलेटरी बॉडीज़ बना रखी हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ देखती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी देखती हैं, RBI भी देखता है, नाबार्ड भी देखता है, जिसकी वजह से किसी एक बॉडी की न कोई मॉनीटरिंग हो पाती है और न ही किसी एक का दखल या अधिकार हो पाता है । इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के लिए और रूरल ऐंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कोई एक्सक्लुसिव बॉडी बना दें, तो वह ज्यादा इफैक्टिव तरीके से इस चीज को देख सकती है । जैसे होम ट्रेड वाला मामला है, अभी माननीय सदस्य फिल्म स्टार्स का जिक्र कर रहे थे कि शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर वगैरह का पैसा इस कंपनी ने मार दिया । इस कंपनी ने 7-8 करोड़ रुपए में उनको अपने विज्ञापन के लिए साईन किया लेकिन किसी का पैसा नहीं दिया । सब रो रहे हैं । उनका पैसा कहां से निकलेगा ? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गांव वालों को बेवकूफ बनाया है, उन्होंने शहर वालों को भी टोपी पहनाई है । इसलिए मेरा यह मानना है कि इसके लिए मल्टी रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए । इस मामले को JPC को देने से कोई हल नहीं निकलने वाला है क्योंकि 2-3 साल में वह रिपोर्ट आएगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि या तो CBI की जांच का दायरा बढ़ा दिया जाए या सीधे-सीधे इन पर FIR करके इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके उचित कार्यवाही की जाए ।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी 3 मूर्धन्य पत्रकारों, माननीय संजय निरुपम, नरेन्द्र मोहन और राजीव शुक्ल जी ने अपनी-अपनी बातें कहीं । मैं उन बातों को दोहराकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं । मैं राजीव शुक्ल जी की इस बात से असहमत हूं कि चूंकि इस मामले को JPC को सौंपने से इसकी जांच में विलंब होगा, इसलिए उन्हें यह मामला नहीं सौंपना चाहिए । अगर व्यवस्था ऐसी है कि जांच लंबित होती है तो व्यवस्था से पलायन करना कोई समाधान नहीं है ।

एक जांच समिति बनाई भी गई है। जो स्टॉक स्कैम के बारे में चर्चा कर रही है, उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि तात्कालिक रूप से उस जांच समिति का दायरा बढ़ाकर इसको उस जांच समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

दूसरा सुझाव हमारे मित्र प्रफुल्ल पटेल ने दिया कि स्थाई रूप से गड़बड़ियां नहीं हो इसके लिए इन सरकारी बैंकों का नियंत्रण और इसका दायरा रिजर्व बैंक के अन्तर्गत कैसे बढ़ाया जाय, किस तरह से एक विशेष अधिकारी या डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाए जिसके अन्तर्गत कोआपरेटिव सैक्टर हो। श्री राजीव शुक्ल जी ने सफाई दी कि शाहरूख खान को भी ठग लिया,

मैं राजीव शुक्ल जी को बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि जो आईकोन है, चाहे शाहरूख खान हो या सचिन तेंदुलकर हो, इनको रुपयों के लालच में गलत लोगों का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर रुपयों के लालच में शाहरूख खान गलत लोगों का प्रचार करते हैं और उनके प्रचार के कारण लोग भ्रमित होते हैं, इसके बारे में वे नहीं सोचते हैं, उन्हें आठ करोड़ रुपये का लालच था, उन्हें आठ करोड़ नहीं मिला, वह बात अलग है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल : पता नहीं चलता है। पहले तो कम्पनी ठीक चल रही थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : मैं क्षमा चाहता हूं। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, शाहरूख खान मेरे भी उतने ही मित्र हैं जितने कि आपके हैं। लेकिन जो आईकोन हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वे किसी का प्रचार-प्रसार करें तो ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : आपके सबसे अच्छे मित्र अमिताभ जी हैं। ...**(व्यवधान)**... वे भी आईकोन हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : वे भी मेरे मित्र हैं। ...**(व्यवधान)**...**इसीलिए** वह आईसीआईसीआई का कर रहे हैं, इसीलिए वह मारुति का कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : आपको मालूम है कि आईसीआईसीआई में क्या चल रहा है? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : अब जो चल रहा है, वह तो सरकार में चल रहा है, जिसके आप सदस्य हैं। आईसीआईसीआई तो सरकार की है। सरकार का उस पर नियंत्रण है। मेरा यह सुझाव है कि इसको जेपीसी के सुपुर्द उसका दायरा बढ़ाकर कर देना चाहिए। और बाकी शाहरूख खान जानें और लोग जानें, राजीव भाई जानें। धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I am grateful to Shri Sanjay Nirupamji, who has brought this matter to the notice of the Government and to the notice of this House. I am also grateful to all the Members who have participated in this discussion, making some very important and valuable suggestions and raised very relevant and valid points.

Sir, cooperation as a subject is in the State List of the Constitution of India. Banking as a subject is in the Union List. Here lies the dichotomy of Constitutional arrangements, as far as cooperative banks are concerned. As far as powers in regard to incorporation, registration, management, amalgamation, reconstruction or liquidation are concerned, they are exercised by the Registrar of Cooperative Societies of the State Government concerned, under the Cooperative Societies Act. As far as the banking is

2.00 p.m.

concerned, that is regulated by the RBI under the Banking Regulation. Hon. Members were quite right in saying that it is this duality of control which has created many problems for the cooperative sector, especially as far as the cooperative sector has involved in banking, whether urban cooperative banks or district cooperative banks or State cooperative banks.

I am very grateful to the hon. Member, Shri Rahman, for categorically stating in this House that the cooperative movement has played a very important role in the development of the economy of this country, especially the rural economy, and the urban economy in smaller towns and cities. This is a contribution which has to be recognised and, therefore, when we discuss issues involved in this particular case, or any cooperatives, generally, we have to keep in mind the fact that cooperatives have played very important role, that they should be allowed to play the important role and that nothing should be done which will throw the baby out of the bath tub.

This was the sentiment, which was expressed in the other House yesterday, in some other connection. I would like to express in this House that we should definitely apply our mind to the shortcomings in the whole system, but with a view to strengthening the movement rather than weakening it.

I think that should be the basic approach. Now, having said that, there is a point, which has been raised here, as to how the Government has responded to the issues in the co-operative movement. I would like to take the House, through you, Sir, into confidence and would like to point out that we were concerned with the weaknesses in the co-operative structure and it was with that end in view, in April, 1999, I appointed a Committee, under the Chairmanship of the Deputy Governor of the RBI, to look at the whole co-operative credit structure. That report was submitted in July, 2000. We had called a meeting of the State Co-operative Ministers in December, 2000, to discuss the recommendations of the Expert Group, because there were many recommendations, where we could not move forward, except with the very willing and active co-operation from the State Governments. Then, a conference of the Chief Ministers was also called on in August, 2001, because all the issues could not be resolved. That meeting was attended even by the hon. Prime Minister. We discussed the approach to the issues. Then, in that meeting itself, I set up a Committee at the political level,

Chaired by my colleague, Mr. Vikhe Patil, who himself is a very eminent co-operator and consisting of the Co-operative Ministers of selected States, they should sit down and find answers to the problems that we are facing in this. That Committee has submitted its report. The report is being implemented in parts. This year, I have made a provision of Rs. 100 crores. It is a token provision, in order to enable the co-operative banks to shore up their capital adequacy norms. The total amount, of course, is much large -- over Rs. 7,000 crores. We are in touch with the State Governments. We have agreed with the State Governments that we will jointly work on this and make sure that the banks' capital bases are adequately enforced so that they can continue to play the role that they are required to play. I am giving this information to the House in order to make the point that we are aware not only of the importance, but also the problems in the co-operative sector. And we are trying our best, in collaboration and in consultation with the State Governments, to sort out the problems. Here, Sir, what has happened in this case? Because I was myself surprised as to what happened? Why has this fraud or scam -- or whatever name we want to give it -- occurred? I went into this in some detail. When I said that there is no regulatory failure, I should not be misunderstood. Because there are two or three aspects of this. One is that after the Scam of 1992, the Reserve Bank of India had issued very detailed guidelines about trading in Government Securities, about bankers' receipts, and about all these aspects relating to capital markets. I went through those instructions myself and I found that there were as detailed instructions as can really be on any subject. This is one part. So, when I say that there is no weakness in the instructions, this is what I meant, that the instructions are very detailed.

The second one is, it is the regulator which discovered this scam. It found out, towards the end of 2001, that large transactions were taking place in Government Securities. Then they decided to go into this in greater detail. So, both the RBI for urban co-operative banks and the NABARD for the district co-operative banks went into this. They started looking into the books of accounts of the various banks. This is how the fraud in the Nagpur Co-operative Bank came to light. This is how the fraud in other co-operative banks has come to light and the RBI, in collaboration with the State Governments, is now taking preventive action. It is taking action to bring the guilty to book and ensure that they do not go scot-free. These inspections were carried out in February, March and a part of April. We have been in touch with the Government of Maharashtra. As I pointed

out, Sir, some action has already been initiated. When I was talking about the detailed instructions, what are the detailed instructions? The detailed instructions are that, no bank, which wants to deal in the Government securities, will employ brokers. The Nagpur Cooperative Bank was not supposed to deal with a broker at all. The arrangement is that the District Cooperative Bank, which has a constituent SGL account with the Maharashtra State Cooperative Bank, will approach the Maharashtra State Cooperative Bank. Suppose they have some surplus funds, why would they like to invest in Government security? In order to meet the statutory liquidity ratio requirements, which Rahman sahab was referring to. The other thing is, if they have surplus funds, the Government securities are very safe to invest in. So, they would like to make investment in Government securities. Many scheduled banks, public sector banks, are making investments in Government securities. So, they would like to make these investments to meet the SLR requirements and to invest the surplus funds. The instructions are that, each one of them must have a constituent SGL account. Then, they will approach the Maharashtra State Cooperative Bank which has the main SGL account. Suppose the Nagpur Cooperative Bank had wanted to invest Rs. 25 crores, 30 crores, 100 crores, or whatever amount, in the Government securities, they should have approached the Maharashtra State Cooperative Bank. The Maharashtra State Cooperative Bank would, then, have asked a broker, because they would have some brokers on their list. They would have asked a broker. The broker's responsibility is to bring the parties together. That's all. So, they would match the demand and supply. That is the end of their role. So, this money would then get transferred to the institution which is holding the securities, and the securities which they had transferred in the name of the bank that wants to buy. This is how the transaction takes place. Now, in this particular case, the Nagpur Cooperative Bank or the other cooperative banks were not supposed to deal directly with a broker. I will come to the point that Mr. Nilotpal Basu had raised. The Home Trade has got a licence as a broker in equity. It did not even have a licence to deal in Government security. So, when the Home Trade approached these banks that they should deal with the Home Trade, two kinds of irregularities or violations were being done. One, they should not have, at all, dealt with the Home Trade. Second, the Home Trade did not even have a licence to deal in Government securities. So, it is like somebody who has a licence to drive a car, and he starts driving a truck; and somebody -- who should not be dealing with that person -- putting whatever he had in the truck, and the

truck then commits an accident. So, this is what has happened. This is the kind of violation that has taken place. The third violation that has taken place is that, the Home Trade people or the other brokers did not deliver the securities. As was pointed out here, only the photocopies were given. Whoever was dealing with it, should have insisted. "We have given you money. Now, you give us the security." They did not give the security. But there was complicity. As a result, moneys were repeatedly made available to these brokers. That is why I say that it is a pure case of fraud. You are buying something from a person who is not authorised to sell. You are making advance to that person. That person is not delivering it to you. You keep on making advance. You keep on giving the money, in violation of all the instructions. This is under investigation; therefore, I will not venture on opinion. It is likely that this money was diverted to the stock market, that it did not give the return; and, therefore, the whole thing blew up. Now, what is the system of inspection? The system of inspection is...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Please explain about provident fund also. That is a very serious issue.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, as far as the issue of provident fund is concerned, my colleague, Munilalji, is sitting here. It falls within the ambit of the Ministry of Labour. They deal with this subject. And, I am sure, if a demand is raised, a statement should be made on the provident fund scam then that concerned Ministry or the concerned Minister will make a statement. But the *modus operandi* is the same, that in the Provident Fund also, large sums of money were made available for investment in Government Securities; Government Securities were never delivered, and the money just went down the drain. This is what has happened.

Sir, as far as the inspection is concerned, the Reserve Bank of India has very strict rules about it. It is only the well-managed Urban Cooperative Banks which are inspected once in three years by the RBI. Otherwise, the inspection is done once in two years for the weak cooperative banks and for the schedule cooperative banks, it is once a year and as far as the State Cooperative Banks and the District Cooperative Banks are concerned, the NABARD inspects them, once in two years. As has been pointed out here, Sir, there are very large number of these banks, and, therefore, it is not possible for either the NABARD, or, the RBI, to keep on inspecting them every six months or every year. So, this is the pattern which has been evolved.

Sir, a point was made by Nilotpalbabu about the background of this gentleman called, Sanjay Agarwal of Home Trade. The information which I have received was that he was the CEO of Lloyds Brokerage. Lloyds Brokerage was under investigation by the SEBI in 1997; there was some violation noticed by Lloyds Brokerage. After which, he was given a warning by the SEBI. Why he was given a warning only, why no further stringent action was taken is another issue.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, my information is this. While this inquiry was going on, on the basis of which, finally, he was given the warning. The EDTV bought it out for a pittance and it was allowed to be renamed and it was allowed to change its management. All this happened under the nose of the SEBI.

I was making this point for the limited purpose of contesting the first line of the fourth paragraph of your statement which says, you are giving a clean chit to the regulators. Factually, it is not correct; and SEBI has not abdicated its responsibility. And, subsequently, you see they tried for the VAC listing; they did not succeed. Then they tried for the NAC listing, where very serious questions about their funding and promoter composition etc. were brought up, but, still, it was not put under scanner. If it was cracked by the regulator, I think, definitely, some of the illegalities and criminalities in which they have indulged, subsequently, could have been stopped...*(Interruptions)*...

श्री संजय निरुपम : मैं एक जानकारी देता हूं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): पूरा कर लेने दीजिए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : संजय जी, मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, इसके बाद जितने क्लैरिफिकेशन्स पूछने हों पूछ लीजिएगा । Sir the point I was making was that there was this inquiry by the SEBI. In this particular case, SEBI is not directly involved, because SEBI is not the regulator of the debt market, in that sense, it registers brokers both for debt as well as for equity. Now, Sanjay Agarwal and Home Trade was not registered for debt market, as I pointed out. He was registered for the equity market; dealing in the equity market. And the point I was making was that in 1997 some violation was noticed, SEBI issued him a warning, but the warning, according to my information, which has been supplied to me, warning did not debar him from continuing to deal in equity. So, Shri Nilotpalbabu is right in saying that what happened was that Lloyds Brokerage changed its name; it became Euro-Asian Securities, which subsequently became Home Trade. This is the

transformation which has taken place. But, the point I was making was, I don't have the details of what was the delinquency of Shri Sanjay Agarwal in 1997, why he was only given a warning and not debarred at that point of time. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, within a day...*(Interruptions)*... It came down by 150 points.

SHRI YASHWANT SINHA : The fact remains that there was no bar on Sanjay Aggarwal for operating in the equity market, but he did not have the licence to operate in the debt market at all. Home Trade did not have the licence, and their operation, therefore, in Government security markets is nothing but pure fraud. It is misrepresentation, and it has succeeded only because there has been a complicity in these banks which are involved in this fraud. Sir, that was the point that I was making. Now, the questions are raised what is the action that we propose to take. Is this a systemic failure? I will very humbly tell the House from my side that my inquiries do not reveal that there is a systemic failure. The systems are properly in place, but as I was trying to explain that if somebody is determined to violate the system, and he is able to create a complicity across the board, and, then, takes some other banks for the ride, then, it is a pure case of fraud and violation of the rules and regulations which exist, and the law should be allowed to take its course. Sir, the other point which I would like to make is what is the size. Sanjay Nirupamji was saying, may be a thousand crores. Rahman Khan was saying that deposits of the cooperative banks -- all kinds of deposits of all the banks -- are over Rs.150,000 crores. My information is that they are in the neighbourhood of Rs. 80,000 crores. Gujarat banks and the other banks which are involved will show that the size of this fraud is limited. The investigations are still on, at the end of it we will know how many of them are involved and what is the total amount, but the unsettled amount is the amount which I have mentioned in the statement which I read before this House. The size of this fraud is small, and there is no need, therefore, to raise a doubt on the viability of all the cooperative banks in the country. We are all aware of the fact that no bank, howsoever strong it is, will be able to tolerate or survive a run on it. Therefore, I would suggest very humbly that there is no reason to doubt the viability of most of the cooperative banks despite the fact that Madhavpura case has happened, Krushi Cooperative Bank case has happened, that classic cooperative bank in Lucknow took place. There have been some frauds taking place in cooperative banks, but, by and large, I will still say

that the cooperative banking movement is safe, it is secure, and the money of the small investors, which is the concern of the entire House, which is also the Government's concern, is safe. Small investors' money is safe because the erosion in the value of the deposits is very minimum, just two per cent or five per cent. Only in the case of Nagpur Bank, it is a little over 16 per cent. We have the Deposit Credit Insurance Guarantee Fund where, in case, really a failure takes place, then, the interests of small depositors whose deposits are up to one lakh, will be taken care of. We did it in the case of Madhavpura Bank, and from the Insurance Guarantee Corporation, we disbursed something like over Rs. 400 crores to the small depositors. So, the small investors should not be dissuaded from putting his money in the cooperative sector, because there will be no other bank. If some of these cooperative sector banks are abolished, I also raised this point when I was talking to my officers I said, "suppose we cancel the licence of all these, then, what will happen? They told me, "many of the areas in this country will remain unserved by any bank." It is the cooperative banks which are providing that service. So, that is the point which I would like to make. The point is what is the action we want to take in order to bring the guilty to book. Maharashtra Government has on the suggestion of RBI, when this matter was brought to their notice, have taken a number of steps. The issue of coordination among the various agencies which are investigating this matter has been raised. Sir, my information is that the Government of Maharashtra has set up a Task Force with representatives of the CID of the Government of Maharashtra, CBI, Enforcement Directorate, Registrar of Cooperative Societies, Home Department of the Government of Maharashtra. These constitute the Task Force. Now, the issue which has been raised by Sanjay Nirupamji and by some other colleagues in this House is whether we should not hand over the entire investigation to CBI. I have taken up the matter, in a general way, with the Government of Maharashtra. I have written a letter to the Chief Minister. I have pointed out the kind of violations that we have noticed, and I have said, "We expect that the Government of Maharashtra would take a firm action in this case." I will take up this issue with the Government of Maharashtra, and, in consultation with them, if they are agreeable, we have absolutely no difficulty in handing over all these cases to the CBI.

Sir, the other point, which has been made by a number of hon. Members in this House, is the issue whether we can refer this case also to the JPC. This is a matter which I will discuss with my colleague, the Minister of Parliamentary Affairs. The JPC's term has just been extended

until the end of the next Session, which is the Monsoon Session. We will discuss it in Government and, on the face of it, I would like to say personally, on my behalf, that I see no objection in referring this matter to the Joint Parliamentary Committee, which is already looking at the market scam. But since it also involves the State Government, I think it will be fair on my part to consult with my colleagues, and make sure that there are no constitutional issues which are raised in this matter. So, we will certainly look at this.

Sir, I am not here to defend any failure on the part of any regulator. If we notice any weakness in the system, we will have no hesitation in taking steps to ensure that those weaknesses are immediately removed.

Finally, Sir, I would like to finally share just one information with this House. I have here the information of action taken with regard to only Urban Cooperative Banks from 31.03.1998 : Licences have been cancelled or rejected of 62 such banks, between these four years; show cause notices have been issued to 15 banks; applications for licence rejected of 24 banks; and specific directions have been issued by the RBI under Section 35 to 45 banks. So, it is not that when we notice weaknesses, action is not taken. Action is taken; some time very drastic action has been taken. And, therefore, Sir, as far as the regulator is concerned, -- Mr. Raghavan has raised that point -- I would very, very humbly suggest, Sir, -- I would like to make this point in all humility -- the RBI is not merely the regulator of the Banks. The RBI is the final monetary authority of this country. The RBI is a very, very respected institution of this country, and we should not be very free with our criticism of the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India has a reputation which is international. They are counted -- and I can say without fear of contradiction -- as one of the best Central Banks in the world. That is the reputation of the RBI. So, let us not do something, without adequate reason, which will detract the reputation which the Reserve Bank of India, Sir, has built.

With these, Sir, I would like to finish my speech.

श्री संजय निरुपम : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । होम ट्रेड को जो बिग लिस्टिंग मिली, वह पुणे स्टॉक एक्सचेंज में मिली और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने इसकी लिस्टिंग लगातार रिजैक्ट की है । जिस दिन यह पूरा स्कैम निकल कर आया, उसके तीन दिन पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने इसको एक लिस्टिंग दी थी । फिर जैसे ही स्कैम निकल कर आया तब बाद में यह लिस्टिंग कैंसिल की गई । तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि

यदि किसी स्टॉक मॉर्केट में किसी एक ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म को लिस्ट करने से मना किया जाए तो पूरे हिन्दुस्तान के किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टिंग न मिले ?

श्री मूल चन्द मीणा : सभापति जी, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सहकारी बैंकों के प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है । मंत्री महोदय ने केवल महाराष्ट्र के 7 बैंकों का ही नाम बताया है, जबकि देश के अंदर बहुत सारे सहकारी बैंक हैं जिनमें ये घोटाले हो रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किस-किस स्टेट में, कितने-कितने बैंक हैं, जो कि प्रतिभूति घोटाले किए हुए हैं ।

SHRI K. RAHMAN KHAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to seek two clarifications from the hon. Finance Minister. About the dual control, he said that there is a constitutionality involved, because cooperative is a State subject. It is also in the Concurrent List. Sir, what I would like to say, because this is one thing ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप एक्सप्लेन मत कीजिए ।

श्री के0 रहमान खान : तो इस डुअल कंट्रोल को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है क्योंकि यह डुअल कंट्रोल जाना चाहिए और रिजर्व बैंक या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी का ही कंट्रोल होना चाहिए । इस बारे में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ? दूसरी बात, यह है कि डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस/कार्पोरेशंस के बैंक्स पूरे डिपॉजिट के ऊपर प्रीमियम देते हैं ...**(व्यवधान)**... लेकिन यह जो एक लाख की रकम रखी गयी है, क्या यह रकम बढ़ाई जा सकती है?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, when I spoke of regulatory failure, I was actually talking about the regulatory inadequacy to really regulate all these. I think the point has been accepted by the hon. Finance Minister when he said that NABARD does not have the wherewithal to improve or to reimpose... In that sense, what is the corrective step that the Government is going to take?

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: उपसमाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एन0पी0एज0 के बारे में कुछ नहीं कहा है । मान्यवर, इकॉनोमिक टाइम्स में एक न्यूज आइटम छपा है जिस की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं Gross NPAs as of March 1999 were to the tune of Rs.2,000 crores.....

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप पूरे डिटेल में मत जाइए ।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : महोदय, मैं कोऑपरेटिव बैंक्स के एन0पी0एज0 की बात कर रहा हूं। The present NPAs have crossed to more than Rs.7,000 crores. तो यह बढ़ाते जा रहे हैं । इसलिए इस के बारे में मंत्री जी बताएं तो उचित होगा ।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, it is not our intention to denigrate the Central Bank of the country. We have high respect for it as

everybody has, but the only point is, as the hon. Minister has said there is inadequacy of the RBI to control all these things. I would like to know whether the Finance Minister will consider having some in house machinery under the control of the RBI, so that it can monitor the performance of non-banking institutions.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN (Maharashtra): Sir, in view of the comment made by the hon. Finance Minister about the inadequacy of the machinery under the control of the RBI, I would like to ask him whether he will consider having a regulator independent of the RBI.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I wanted the hon. Minister to respond on the idea of creating an exclusive regulatory body instead of a multi-regulatory body.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, the hon. Minister was referring to the weaknesses in absorbing the system. He said they will be duly corrected. My clarification is whether some weaknesses have been observed in the system or the financial system itself is very weak. Scams are taking place perpetually every now and then. Nowadays, in every Parliament session one scam or another scam is being discussed. Will you ensure that corrective measures will be taken? It is high time that you adjust the system to rid of the weaknesses.

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Sir, when I referred to RBI, it was in my mind that the RBI representatives in various institutions do not perform their duties.

श्री नरेन्द्र मोहन : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट हूं, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो एक बात जानना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...क्या रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिस से कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है ? अगर ऐसे सुझाव आए हैं तो कृपया बताएं ।

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि संजय निरूपम जी ने जो पाइंट उठाया कि एक जगह अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसके बेसिस अन्य जगह भी डीलिस्ट कर सकते थे । इस पर मैं सेबी के साथ चर्चा करूंगा कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है या इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि होम ट्रेड को इक्विटी में डील करने का लाइसेंस था और उसने सिक्युरिटीज में डील किया । यह उसने नियमों का, कायदे-कानूनों का उल्लंघन किया और इसलिए सेबी ने, मेरी सूचना के अनुसार, उसका इक्विटी डील करने का जो लाइसेंस था उसको निरस्त कर दिया है । इसके अलावा सेबी ने और भी एहतियातन कई स्टेप लिए हैं ताकि इसका असर स्टॉक एक्सचेंज पर न आए । ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरूपम : सर, मुम्बई में रोका गया, लेकिन ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... माननीय संजय निरूपम जी, अब आप आसन ग्रहण करें।...**(व्यवधान)**... बसु साहब, नहीं । ...**(व्यवधान)**... अब आप बैठें ।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Listing was not recommended even in Mumbai. Listing of Home Trade was not recommended. The Danuka Committee, every Committee, rejected it. But, suddenly, listing was given in Mumbai. That needs to be investigated.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the other point which has been raised by Rahman Saheb is whether in this Insurance Deposit Guarantee Corporation, an amount beyond Rs.One lakh can be raised. It is a suggestion for action. I am taking note of it.

Sir, on the issue of whether this kind of violation has been noticed in other States also, I would like to say that according to my information, there are eight urban cooperative banks in Gujarat where also this has been noticed. There is one rural bank in Orissa where we have noticed a similar situation through the same broker, namely, Home Trade. Obviously, Home Trade was trying to cast its net as wide as possible. And the investigations are still on. The Reserve Bank of India has taken up the inspection of a number of urban cooperative banks. They have asked the State Governments to get the accounts audited of others. The NABARD is also on the job. We will know the extent of this very soon...*(Interruptions)*...

But the most important question, Sir, is whether we are in a position to have a non-RBI, independent, regulator. This is the point which has been raised. That is an exclusive regulator separate from RBI. I think Mr. Ramachandraiah was making the suggestion whether for non-banking finance companies and for urban cooperative banks, we can have a regulator, a separate arrangement within the RBI. Now, we already have a separate arrangement within the RBI as far as the role of the RBI as a regulator is concerned. On this issue, a separate regulator is not going to solve the problem. How will you have the separate regulator function differently from the RBI until the arrangement is changed, until there is just one authority, which will be responsible for everything as far as cooperative banks are concerned? And that is something, which is a rather delicate issue. This is something, which we are in the process of discussing with the State Governments, of which I have given here the account. So, until that situation is evolved in consultation with and with the concurrence of the

State Governments, it will be somewhat difficult to just create another regulator, which will face the same handicap that the RBI is facing. It will, certainly. It has been the endeavour of the RBI, and that is the point which I have made, to ensure that they do their job and ask the NABARD and other regulators like NHB, SIDBI, etc., to do their job, in turn, as sincerely as possible. And that is the direction in which we would like to take this policy. Our discussions with the State Governments are continuing and if we are able to evolve a consensus, as I said, we will certainly think of it.

PAPERS LAID ON THE TABLE - *Contd.*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Status Paper on Indian Railways - Issues and Options.

GOVERNMENT BILLS

THE PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 2002

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI MUNI LAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : प्रश्न यह है ...*(व्यवधान)*...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): सर, हमारा एक निवेदन है ...*(व्यवधान)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh) : Sir, there is one important Bill which was passed by the Lok Sabha yesterday; the Cable T.V. Network (Regulation) Bill. It should be taken up in the House. Tomorrow happens to be a day for the Private Members Business; we won't have a chance to discuss this Bill.

SOME HON. MEMBERS: No, no; it can't be taken up. There is no time for it.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu) : Sir, it is not listed in the List of Business. ...*(Interruptions)*... The Bill has not been circulated.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, because of its importance, our C.M. has written a letter to the Prime Minister also.